हिंदी दैनिक

कलम की पहल

PRGI NO. UAHIN/25/A1323

वर्ष : 02 अंक : 158 पृष्ठ : 08 मूल्य : 1 रूपए नैनीताल, गुरूवार, 26 नवंबर, 2026

E-mail: kalamkipahaluk@gmail.com Website: kalamkipahal.com

'ड्रग मनी' हिंद महासागर के लिए बड़ा खतरा, मिलकर रोकना होगा: एनएसए डोभाल

नई दिल्लीः मालदीव की राजधानी माले में बुधवार को कोलंबो सिक्योरिटी कांउसिल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 8वीं बैठक आयोजित की गई. इसमें भारत के एनएसए अजित डोभाल ने हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता और साझा विरासत पर जोर दिया. ड्रग तस्करी को लेकर फिक्र जाहिर जताते हुए उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका, मालदीव समेत अन्य देशों के साथ जानकारी साझा कर इस पर काम कर रहा है और अब इस सहयोग को और आगे बढ़ाने की जरूरत है.

अजित डोभाल ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की यात्रा में योगदान देने वाले सभी सदस्य देशों का धन्यवाद किया. डोभाल ने कहा, 'हमने एक शुरुआती विचार से शुरुआत की थी कि हिंद महासागर हमारी राष्ट्रीय



सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, हमारी आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र के लोगों के हितों के लिए भी महत्वपूर्ण है.' उन्होंने कहा, ' सभी के सहयोग से आज इस मंच के पास अपना सचिवालय है, अपने महासचिव हैं और आने वाले समय में इसे और आगे ले जाने की उम्मीद है. हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देश एक साझा समुद्री क्षेत्र साझा करते हैं और एक सभ्यतागत विरासत से जुड़े हैं जो लंबे इतिहास में आकार ले चुकी है. हमारी परंपरा हमें समुद्र के माध्यम से जोड़ती है, बांटती नहीं.

डोभाल ने याद दिलाया कि नवंबर 2020 में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का गठन हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षा और स्थिरता के सामूहिक विजन के साथ किया गया था. उन्होंने कहा, 'संगठनात्मक जड़ें जमाने के साथ-साथ सीएससी को एक एक्शन-ओरिएंटेड मंच में बदला गया है, जहां सहयोग सभी सदस्य देशों के आपसी लाभ को प्राथमिकता देता है.' उन्होंने कहा कि समुद्री सुरक्षा और संरक्षा, आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला, साइबर सुरक्षा और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मजबूत सहयोग जारी है. यही सहयोग सीएससी की भावना को परिभाषित करता है.

बैठक में ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के प्रतिनिधियों की मौजूदगी पर खुशी जताते हुए डोभाल ने उम्मीद जताई कि ये विशिष्ट अतिथि भविष्य में इस मंच से जुड़ेंगे. भारत के एनएसए ने आगे कहा, 'अब तक हमने बीते हुए कल की चुनौतियों पर विचार रखे. अब हमें आने वाले कल की चुनौतियों को लेकर तैयार रहना है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीकें दुनिया को पूरी तरह से नए संघर्ष और सहयोग के क्षेत्र में ले जाएंगी.' सामूहिक प्रयास को जरूरी बताते हुए डोभाल ने आगे कहा, 'तकनीक, सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग से हम कई और विविध क्षेत्रों में एक साथ काम कर सकते हैं.' उन्होंने कहा कि सीएससी की भावना के अनुसार, इन चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों को मजबूत करना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है.

आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट का आदेश किया रद्द

दिल्लीः कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है. HC ने CBI और ED को राहुल गांधी के खिलाफ उन शिकायतों की जांच करने को कहा गया था कि उनके पास उनकी आय से अधिक संपत्ति है. सुप्रीम कोर्ट ने BJP सदस्य विग्नेश शिशिर की याचिका को हाई कोर्ट के पास वापस भेज दिया ताकि वो इस पर नए सिरे से विचार कर सके. इसमें याचिका के सुनवाई योग्य होने का सवाल भी शामिल है.सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राहुल गांधी को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2026 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसमें सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) को राहुल गांधी की संपत्ति की जांच करने के निर्देश दिए गए थे.कोर्ट ने इस बात पर फोकस किया कि हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की बात सुने बिना आदेश कैसे



जारी कर दिया. साथ ही अदालत ने CBI और ED को भी निर्देश दिया था कि वे फिलहाल हाई कोर्ट के सामने इस मामले में कोई रिपोर्ट दाखिल न करें.

27 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को बिना किसी आधार के उठाने वाले एक वकील को फटकार भी लगाई थी. दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई हुई थी. CJI ने कहा था कि इस मामले को उठाने की बात में न तो कोई स्पष्ट आधार है और न ही कोई ठोस मतलब है. अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया है.

कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत के बात ये पूरा मामला शुरू हुआ था. उन्हों राहुल गांधी की संपत्ति को लेकर कई तरह के आरोप लगाए थे.कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता, सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था.दरअसल राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी.

केदारनाथ में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रोपवे, गौरीकुंड से 16 KM का सफर सिर्फ 36 मिनट में होगा, 9 घंटे की लंबी चढ़ाई खत्म

केदारनाथः उत्तराखंड की चारधाम यात्रा केदारनाथ सबसे अहम तीर्थस्थल है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 5000 करोड़ के केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का खाका पेश किया है. ये पीपीपी के बीओटी मॉडल पर रोपवे बनेगा. इससे सरकार को सालाना 800 करोड़ की आय होगी. उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट सबसे दुर्गम तीर्थयात्रा को बेहद आसान कर देगा. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में मंगलवार को एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी. केदारनाथ रोपवे लगभग 11500 फीट की ऊंचाई पर रोपवे दुनिया के सबसे लंबे और ऊंचे रोपवे में से एक होगा.



13 किमी रोपवे सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक हवाई कनेक्टिविटी देगा. रोपवे की हर ट्रॉली-केबिन में करीब 35 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी.अभी सोनप्रयाग या गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक श्रद्धालुओं को 16 किमी की यात्रा में लगभग 8 से 9 घंटे लगता है. रोपवे से यह दूरी मात्र 36 मिनट में होगी. इस परियोजना की लागत लगभग करीब 5 हजार करोड़ होगी.

11500 फीट की ऊंचाई पर रोपवे दुनिया के सबसे लंबे और ऊंचे रोपवे में से एक होगा

13 किमी रोपवे सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक कनेक्टिविटी देगा

27 से 36 मिनट में तय होगी गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की यात्रा

16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़नी होती है अभी यात्रा में

रोपवे प्रति घंटे 1800 यात्रियों को ले जा सकेगा बेस कैंप से

18 हजार यात्री रोजाना रोपवे का फायदा उठा सकेंगे

5000 करोड़ का केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट

800 करोड़ रुपये की सालाना आय होगी सरकार को

27 से 36 मिनट में केदारनाथ यात्रा होगी

चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग या गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़नी होती है.

बीजेपी नेता योगेश गौड़ा हत्याकांड में पूर्व कांग्रेस विधायक समेत अन्य दोषियों को SC से झटका, जमानत रद्द, दो हफ्ते में करना होगा सरेंडर

नई दिल्ली। सप्रीम कोर्ट से साल 2016 में बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की हत्या मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी समेत अन्य दोषियों को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत देने के आदेश को रद्द कर दिया. अब पूर्व विधायक और दोषियों को दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करना होगा. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने हाईकोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए कुलकर्णी और अन्य दोषियों की जमानत भी रद्द कर दी.

सभी दोषियों को दो हफ्ते के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश



दिया.आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आपराधिक अपील में चुनौती दिए गए आदेश निरस्त किए जाते हैं.दोषी द्वारा प्रस्तुत जमानत बांड रद्द किए जाते हैं और उन्हें दो सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा.सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा.

दरअसल, 31 जुलाई 2026 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने कुलकर्णी की दोषसिद्धि पर उनकी अपील के निस्तारण तक रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने उनकी उम्रकैद की सजा निलंबित कर कुछ शर्तों के साथ पांच लाख रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया था.साथ ही अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ने और अदालत के निर्देश पर पेश होने से संबंधित शर्तें भी लगाई गई थीं. हाईकोर्ट ने अन्य दोषियों की सजा भी अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दी थी.

यह मामला 2016 में धारवाड़ में बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा की हत्या से जुड़ा है. योगेश गौड़ा की धारवाड़ के सप्तापुर इलाके स्थित उनकी जिम में हथियारबंद हमलावरों ने हत्या कर दी थी.शुरुआत में धारवाड़ पुलिस ने मामले की जांच की और छह लोगों को गिरफ्तार कर आरोपपत्र दाखिल किया. बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई.

चले थे भारत को तोड़ने, खुद हो गए दो फाड़; PoK में भड़के विरोध-प्रदर्शन से ISI और JeM में ही दरार

नई दिल्ली। पाकिस्तान के कब्जे वाले यानी पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में पिछले कुछ समय से स्थानीय लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किए हुए हैं। ये लोग महंगाई, आटे-बिजली की किल्लत और बुनियादी सुविधाओं की मांग पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, कोटली, मीरपुर और धीरकोट सहित कई इलाकों की सड़कों पर उतर कर हंगामा कर रहे हैं। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के नेतृत्व में चल रहे इन प्रदर्शनों



को कुचलने के लिए पाकिस्तान सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने जिस तरह के हथकंडे अपनाए हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ISI ने PoK में जिस तरह की बर्बरताएं की हैं, उसकी वजह से ISI और आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) में फूट पड़ गई है।

दरअसल, भारत को तोड़ने की साजिश रचने वाला आतंकी संगठन JeM पिछले साल मई में हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद से काफी हद तक निष्क्रिय रहा है लेकिन PoK में जारी विरोध-प्रदर्शनों को लेकर पाकिस्तानी प्रशासन के रवैये से जैश के कुछ सदस्य नाराज हो गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले छह महीनों में विरोध-प्रदर्शनों से निपटने के पाकिस्तानी सरकार के तरीके से इस आतंकी संगठन के कुछ सदस्य खुश नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाए हैं कि बुनियादी अधिकारों, बेहतर नागरिक सुविधाओं और जीवन स्तर में सुधार की मांग कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इतनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल क्यों किया गया? पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) और जैश-ए-मोहम्मद के बीच तकरार इस हद तक पहुंच गया है कि ISI ने हाल ही में JeM को एक डोजियर सौंपा है।

इसमें संगठन के नेतृत्व से कहा गया है कि वे कम से कम 23 ऐसे सदस्यों को काबू में रखें, जो रावलकोट में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों में शामिल हो गए थे।

होशियारपुर की सोनालिका फैक्ट्री में घुसा तेंदुआ, मचा हड़कंप, हजारों कर्मचारियों की छुट्टी !

होशियारपुर। सुबह-सुबह फैक्ट्री खुली तो ट्रैक्टर नहीं, तेंदुआ निकला! पंजाब के होशियारपुर की मशहूर सोनालिका इंटरनेशनल फैक्ट्री में ऐसा मंजर देखने को मिला कि बड़े-बड़े इंजीनियर और मजदूर भी दहशत में आ गए. रात के अंधेरे में चुपके से एक तेंदुआ फैक्ट्री कम्पाउंड में घुस गया और फिर वहीं छिपकर बैठ गया. सुबह जब कर्मचारियों को पता चला कि फैक्ट्री के अंदर ट्रैक्टर बनाने वाली मशीनों के बीच खूंखार तेंदुआ घूम रहा है, तो हड़कंप मच गया. आनन-फानन में कंपनी प्रबंधन ने बड़ा फैसला लिया. सुरक्षा के मद्देनजर सभी कर्मचारियों और स्टाफ को छुट्टी देकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

सोनालिका फैक्ट्री का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तेंदुआ घूमते हुए नजर आ रहा है. उधर, कर्मचारियों को छुट्टी देने के बाद फैक्ट्री में सन्नाटा छा गया, मशीनें थम गईं, लेकिन बाहर पुलिस, वन विभाग और लोगों की भीड़ जुट गई. बताया जा रहा है कि तेंदुआ बीती रात से ही फैक्ट्री परिसर के अंदर मौजूद है. सोनालिका के कर्मचारी अतुल शर्मा ने बताया कि रात से ही तेंदुआ अंदर है.

फैक्ट्री में भारी मशीनरी और बड़ी संख्या में उपकरण लगे होने के कारण तेंदुए की सही लोकेशन का पता लगाने में टीमों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

ऑक्सफोर्ड जाने से रोके गए सौरव दास दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे; अब गुरुवार को सुनवाई

नई दिल्लीः कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास को यूके जाने से रोके जाने का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. दास ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लंदन जाना था, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें यात्रा करने से रोक दिया. उनका कहना है कि न तो उन्हें किसी प्रतिबंधात्मक आदेश की जानकारी दी गई और न ही कोई औपचारिक दस्तावेज दिखाया गया. मामले की सुनवाई अब गुरुवार को होगी. सौरव दास की ओर से उनके वकील ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के



समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा गया कि दास को यूनाइटेड किंगडम जाना है और यदि मामले पर शीघ्र सुनवाई हो जाए तो वह 27 नवंबर तक अपने कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. दास के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर रोक दिया गया था. उन्होंने कहा कि दास को कोई आदेश नहीं दिखाया गया और न ही यह बताया गया कि उनके खिलाफ कोई लुकआउट सर्कुलर (LOC) या यात्रा प्रतिबंध लागू है. इसी आधार पर अदालत में नई याचिका दाखिल की गई है. सौरव दास का कहना है कि उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की ओर से एक पैनल चर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था. उनके अनुसार, यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) और एडिनबर्ग जैसे संस्थानों में 'कॉकरोच मूवमेंट' विषय पर व्याख्यान देने के लिए भी आमंत्रण मिला था.

मेरे कपड़ों से चिढ़ होती है तो होने दीजिए, कट्टर हिंदू नेता की छवि पर बोले योगी

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर किसी को मेरे वस्त्रों से चिढ़ होती है तो होने दीजिए। हम बहुत ज्यादा इसकी चिंता नहीं करते। अब मैं किसी के कारण अपना वस्त्र थोड़े उतारूंगा। अपने पारंपरिक भगवा वस्त्रों को लेकर इंटरनेशनल मीडिया के एक तबके द्वारा कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर पेश किए जाने को लेकर पूछे एक सवाल पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे अपने सनातन धर्म, देश और हिंदू होने पर गौरव की अनुभूति होती है। दुनिया चाहे जो भी सोचे। यदि कोई कहे कि आप इनको छोड़ दें और हम आपको सपोर्ट करेंगे तो मैं कहूंगा कि तुम अपने यहां रहो हम अपने दम पर अचीव कर लेंगे। हमें किसी की मेहरबानी



नहीं चाहिए।

शिखर सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर और विकसित भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर और विकसित यूपी को हम यूपी के युवाओं के दम पर आगे बढ़ाने में समक्ष हैं और इसको आगे बढ़ा देंगे। सीएम योगी ने बताया कि मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे स्थापित हो रहे लॉजिस्टिक सेंटर का उल्लेख करते हुए बताया कि वहां एक अमेरिकन कंपनी 3 हजार करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। सीएम ने कहा कि डेटा सेंटर कलस्टर जो एआई की बुनियादी आवश्यकता है यूपी में बन रहा है। सेमी कंडक्टर की यूनिट यूपी में लग रही है।

लखनऊ को हम एआई सिटी के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। यूपी के अंदर कोई सोचता कि ड्रोन टेक्नालॉजी का हब बनेगा? रोबोटिक का सेंटर यूपी बनेगा? आज ये सब हो रहा है। डिफेंस मैनुफैक्चरिंग कॉरीडोर में भी यूपी ने जो अभूतपूर्व छलांग लगाई है वो अद्भुत है। उनकी आंखे चौंधिया जाएंगी ये सब देखकर। सीएम योगी ने कहा कि किसी को मेरे वस्त्रों से चिढ़ होती है तो होने दीजिए। हम इसकी बहुत चिंता नहीं करते हैं। अब किसी के कारण मैं अपने वस्त्र थोड़े उतारूंगा।

सीएम योगी ने कहा कि वह तो जापान, यूके, रूस सब जगह अपने यही वस्त्र पहनकर गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं भारत की उस संन्यास परम्परा से आता हूं जिसके मन में देश और धर्म के लिए त्याग और बलिदान की परंपरा है और हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा कितने टिकट काटने वाली है? के सवाल पर सीएम योगी ने विधायकों के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि एनडीए के विधायकों ने जितना काम पिछले 10 साल में किया है उनसे पहले किसी विधायक ने नहीं किया।

पीआरडी जवानों के कार्य बहिष्कार से हिली विभागीय व्यवस्था

329 जवानों ने शुरू किया आंदोलन, समान वेतन और 365 दिन ड्यूटी की मांग पर आर-पार की लड़ाई

के.के.पी संवाददाता

चंपावत। महज 650 रुपये प्रतिदिन के मानदेय पर परिवार का भरण-पोषण करने की मजबूरी और सालभर नियमित ड्यूटी की मांग को लेकर पीआरडी जवानों का आक्रोश अब सड़कों पर उतर आया है। 48 महिलाओं समेत जिले के 329 पीआरडी जवानों ने बुधवार से सामूहिक कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। जवानों के आंदोलन से विभिन्न विभागों की व्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। इससे साफ हो गया है कि विभागीय व्यवस्थाओं में पीआरडी जवानों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।



दो सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे जवानों ने तीन दिवसीय कार्य बहिष्कार का अल्टीमेटम देने के बाद जिला युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन शुरू किया। जवानों ने एकजुट होकर सरकार से समान कार्य के लिए समान वेतन और 365 दिन नियमित ड्यूटी की व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई। पीआरडी जवान हित संगठन के अध्यक्ष भैरव जोशी ने कहा कि जवान शौकिया तौर पर आंदोलन नहीं कर रहे हैं। उनकी पीड़ा यह है कि 650 रुपये प्रतिदिन के मानदेय पर परिवार का पालन-पोषण करना बेहद मुश्किल हो गया है। सालभर नियमित ड्यूटी नहीं मिलने से जवानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब जवान विभागीय कार्यों में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो उन्हें भी सम्मानजनक वेतन और नियमित रोजगार मिलना चाहिए।

धरना स्थल पर विनोद सिंह, जीवन कापड़ी, अनीता महर, सुनीता मेहता और दीपक मेहता ने भी विचार रखे। जवानों ने मांगों के समाधान तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। अध्यक्ष भैरव जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बुधवार को देहरादून में मुख्य सचिव द्वारा संगठन के प्रांतीय नेतृत्व से वार्ता की जानी है। वार्ता में मांगों पर क्या निर्णय होता है, इसके बाद ही आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी।

बाल विवाह और बाल अपराधों से मुक्ति का संकल्प, चम्पावत में कार्यशाला, जिलाधिकारी ने बाल विवाह मुक्ति रथ को दिखाई हरी झंडी

2030 तक देश को बाल अपराध से मुक्त करने का संकल्प, जिले में बाल विवाह की घटनाओं को शून्य पर लाने का लक्ष्य

के.के.पी संवाददाता

चम्पावत। मॉडल जिले को बाल विवाह और बाल अपराधों से मुक्त करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यशाला में आज 2030 तक पूरे देश को बाल अपराध से मुक्त करने का संकल्प लिया गया। विकास भवन में इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, किच्छा के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी अजय सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि बच्चों का अपना स्वच्छंद संसार होता है और उन्हें उड़ने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। बच्चों को हम जैसे संस्कार देंगे, वे उनके जीवन मार्ग को आलोकित करेंगे। उन्होंने चम्पावत जिले में बाल विवाह की



सर्वाधिक संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि यह सबके लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

इंस्टिट्यूट के निदेशक डॉ. अमित श्रीवास्तव ने कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने शादी के नाम पर बाल ट्रैफिकिंग, बाल विवाह मुक्ति, किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम सहित बच्चों से संबंधित अपराधों की जानकारी देते हुए कहा कि इस महान कार्य के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। इस अवसर पर राकेश श्रीवास्तव ने जादू के माध्यम से विषय को और प्रभावी ढंग से समझाया। इससे पूर्व जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बाल विवाह मुक्ति रथ को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है और उनके प्रति हमारी संवेदनाएं उनका भविष्य सुनिश्चित करने में मदद करती हैं। उन्होंने इंस्टिट्यूट के निदेशक को आश्वस्त किया कि हम सब मिलकर चम्पावत जिले में सर्वाधिक बाल विवाह की घटनाओं को शून्य पर लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही 2030 तक राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप स्वयं को तैयार करेंगे, जिसके लिए सभी को अभी से कमर कसनी होगी। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी आरएस सामंत, आईसीडीएस के अधिकारियों समेत अर्जुन सिंह, मीनू पंत सहित कई लोग मौजूद रहे।

एक नजर

अग्निवीर भर्ती रैली के तीसरे दिन 850 से अधिक युवाओं ने लगाई दौड़, 674 रहे सफल

गुरुवार को चम्पावत, पाटी और पूर्णागिरि तहसीलों के अभ्यर्थी लेंगे भाग



के.के.पी संवाददाता/चम्पावत। बनबसा सैन्य स्टेशन के मैदान में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के तीसरे दिन बुधवार को पिथौरागढ़ जिले की कनालीछीना, बेरीनाग, धारचूला, डीडीहाट, पांखू और देवलथल तहसीलों के 850 से अधिक युवाओं ने दौड़ में भाग लिया। नौ बैचों में आयोजित दौड़ में 674 अभ्यर्थी सफल रहे।

सुबह से ही सेना के जवानों ने अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच कर उन्हें रैली स्थल में प्रवेश दिया। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कर उन्हें शारीरिक परीक्षण के अगले चरण के लिए भेजा गया। तीसरे दिन दौड़ में सफल रहे अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण गुरुवार को होगा, जबकि पहले और दूसरे दिन सफल रहे अभ्यर्थियों के चिकित्सकीय परीक्षण जारी हैं।

जोनल भर्ती कार्यालय (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड) के अधीन सेना भर्ती कार्यालय, पिथौरागढ़ की ओर से आयोजित इस रैली का संचालन भर्ती निदेशक कर्नल अमोल दबड़घाव के निर्देशन में किया जा रहा है। अभ्यर्थियों के प्रवेश, दस्तावेजों की जांच और दौड़ की व्यवस्था सेना के अधिकारियों और जवानों ने संभाली। रैली के चौथे दिन गुरुवार, 26 नवंबर को चम्पावत जिले की चम्पावत, पाटी और पूर्णागिरि तहसीलों के अभ्यर्थी दौड़ में भाग लेंगे।

पाटी महाविद्यालय में कल मनेगा संविधान दिवस

के.के.पी संवाददाता/चम्पावत। माय भारत के तत्वावधान में कल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पाटी में नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट और विकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रम के तहत संविधान दिवस मनाया जाएगा। इसमें प्रस्तावना का वाचन और संविधान के महत्व पर चर्चा होगी। उद्देश्य युवाओं को संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक कर लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है।

27 साल बाद फौजी चंद्रशेखर बगोली को भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में जगह, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

1998 में सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भाजपा से जुड़े, फोर्ती गांव के दो बार रहे ग्राम प्रधान

के.के.पी संवाददाता/लोहाघाट। निकटवर्ती फोर्ती गांव के फौजी चंद्रशेखर बगोली को भाजपा ने प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया है। चंद्रशेखर वर्ष 1998 में सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद वे भाजपा की राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर पार्टी में शामिल हुए और सामाजिक कार्यों से जुड़ गए। उन्होंने भाजपा संगठन को मजबूत करने का काम शुरू किया। कार्यकर्ताओं के अनुसार उन्होंने जनसेवा के उद्देश्य से ही भाजपा का दामन थामा था और बदले में उनकी कोई अपेक्षा नहीं थी।



अपने गांव के लोगों की सेवा करते हुए फोर्ती गांव के लोगों ने उन्हें दो बार ग्राम प्रधान चुना। उनके बेटे संदीप बगोली भी समाज सेवा के कार्यों में परछाई की तरह पिता का हाथ बंटाते रहे। एबीवीपी से जुड़े संदीप की सेवाओं को देखते हुए स्वामी विवेकानंद पीजी कॉलेज के छात्रों ने उन्हें छात्र संघ अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया। चंद्रशेखर को प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किए जाने का पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि एक निस्वार्थ जनसेवक को पार्टी द्वारा दिया गया यह सम्मान सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है।

बगोली ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसे नेता मिले हैं, जिनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री धामी देवभूमि के देवत्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके हाथ मजबूत करने की हम सबकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है।

संवैधानिक मूल्यों और नागरिक जिम्मेदारियों पर छात्राओं को किया जागरूक

के.के.पी संवाददाता

अल्मोड़ा। पीएम श्री राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बाड़ेछीना में बुधवार को नागरिकता कौशल, संवैधानिक मूल्यों एवं भारत का ज्ञान विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) अल्मोड़ा से आमंत्रित मुख्य वक्ता डॉ. प्रकाश चंद्र पंत ने छात्राओं को नागरिकता के अधिकारों एवं कर्तव्यों, भारतीय संविधान के मूल्यों, लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा देश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय विरासत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉ. पंत ने छात्राओं को जागरूक, जिम्मेदार एवं कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने संविधान के प्रति सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ और नागरिक जिम्मेदारियों के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के शुभारंभ पर प्रधानाचार्या ने



आमंत्रित अतिथि का स्वागत एवं सम्मान किया। विद्यालय की बाल संसद के सदस्यों ने भी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर छात्राओं के लिए निबंध प्रतियोगिता सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को मुख्य वक्ता डॉ. प्रकाश चंद्र पंत ने पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षिकाएं प्रीति पंत, शिप्रा बिष्ट, तनुप्रिया खुल्बे, हेमा पटवाल, जानकी राणा, ममता भट्ट, रेखा मेहता, निवेदिता मिश्रा सहित विद्यालय के शिक्षक-कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं में संविधान के प्रति सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ तथा राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदारियों की भावना विकसित करने का प्रयास किया गया।

चम्पावत के ओखलदूंगा के पास स्वयंभू फुटलिंग धाम, चंद्र राजाओं के समय से हो रही है पूजा

गाय के दूध से मिले शिवलिंग की मान्यता, 3 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचते हैं श्रद्धालु

के.के.पी संवाददाता

चम्पावत। मुख्यमंत्री के मॉडल जिले में कण-कण में भगवान शंकर के दर्शन होते हैं। यहां कई ऐसे स्थान हैं, जहां मान्यता है कि जंगल में चरने गई गौ माता ने अपने दूध से शिवलिंगों की खोज कराई और आज वे शिवधाम बनते जा रहे हैं। चम्पावत से 25 किलोमीटर दूर सिपटी से नंदोला के दुनिया ओखलदूंगा गांव के समीप 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद भूमि के गर्भ से स्वयं प्रकट हुए शिव-शक्ति के दर्शन किए जा सकते हैं। बताया जाता है कि चंद्र राजाओं के समय इन फुटलिंगों का पता चला था। उनके सेनापति संग्राम सिंह कार्की ने उसी समय यहां नौला बनवाया, जो आज भी 'कार्की नौले' के रूप में पहचाना जाता है। इसी नौले के जल से फुटलिंग पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता रहा। बाद में सेनापति ने दुनिया ओखलदूंगा के पुरोहितों को फुटलिंग का पुजारी बनाकर पूजा कराई, जो परंपरा आज भी जारी है। यहां चैत्र और अश्विन नवरात्र में सामूहिक पूजा होती है। मान्यता है कि यहां निःसंतान महिलाओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साधनों के अभाव के बावजूद विभिन्न स्थानों से शिवभक्त यहां पहुंचते हैं। करीब 15 वर्षों से विद्वान संत हरभजन गिरी महाराज के यहां आने के बाद

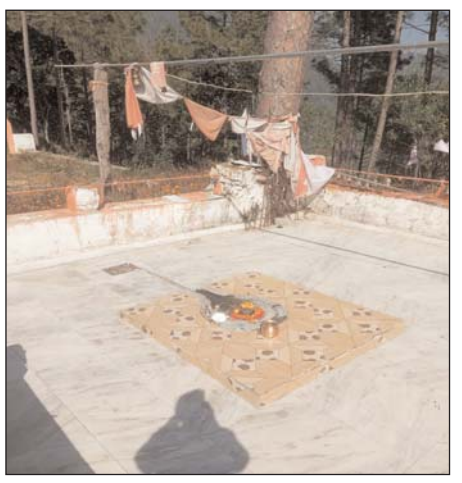

जंगल से घिरे इस शिवालय में पूर्व विधायक हिमेश खर्कवाल ने पानी और बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई थी। पर्यावरण के प्रति जागरूक सागर गिरी महाराज दिन-रात वन्यजीवों के बीच यहीं रहते हैं। उनका कहना है कि फुटलिंग के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण जरूरी है। साथ ही सोलर लाइट लगाने और 3 किलोमीटर तक पक्का रास्ता बनाने की भी मांग की गई है।

कालाढूंगी : रतनपुर बेलपलाव के देवी ब्रह्मचारिणी माता मंदिर में धार्मिक परायण संपन्न



के.के.पी संवाददाता

कालाढूंगी। क्षेत्र के रतनपुर बेलपलाव स्थित देवी ब्रह्मचारिणी माता मंदिर में आज श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ धार्मिक परायण संपन्न हुआ। यह आयोजन कथावाचक श्री कांति बल्लभ पाठक के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। परायण के दौरान मुख्य जजमान के रूप में श्री राजेंद्र तिवारी जी ने धर्मलाभ अर्जित किया। धार्मिक अनुष्ठान व पूजा-अर्चना के कार्य में पंडित प्रकाश चंद गुणवंत और पंडित रमेश पाठक की महत्वपूर्ण भूमिका रही।?इस अवसर पर नवीन तिवारी जी, दीपक तिवारी जी, कैलाश चंद तिवारी, राज तिवारी जी, हम तिवारी जी तथा प्रदीप भास्कर तिवारी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के श्रद्धालु व भक्तजन उपस्थित रहे। सभी भक्तजनों के सक्रिय सहयोग और सहभागिता से आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया और क्षेत्र की सुख-समृद्धि व खुशहाली की कामना की गई।

मतदाता सूची में अपना और परिवार का विवरण जांचें, पात्र युवा नाम जुड़वाने के लिए करें आवेदन: जिलाधिकारी

27 नवंबर तक चलेगा विशेष सत्यापन अभियान, 11 दिसंबर तक लिए जाएंगे दावे और आपत्तियां

के.के.पी संवाददाता

चम्पावत। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे प्रारूप मतदाता सूची में अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम व विवरण जरूर जांच लें। उन्होंने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में दर्ज नहीं है, वे समय रहते आवेदन करें। परिवार और आसपास के ऐसे युवाओं को भी आवेदन के लिए प्रेरित करें, जो पहली बार मतदाता बनने के पात्र हैं। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड के दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण चल रहा है। इसके लिए 1 जनवरी 2027 अर्हता तिथि निर्धारित है। इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। विशेष अभियान के तहत 27 नवंबर 2026 तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने-अपने मतदान केंद्रों की मतदाता सूची का सत्यापन कर रहे



हैं। प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में 11 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। पहली बार नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6, किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के अनुरोध के लिए प्रपत्र-7 तथा दर्ज विवरण में सुधार या निवास बदलने पर मतदाता पंजीकरण नए पते पर स्थानांतरित कराने के लिए प्रपत्र-8 भरें। नागरिक अपने स्थानीय बीएलओ के माध्यम से या संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) के कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। मतदाता सूची में अपना विवरण देखने और ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है।

जिलाधिकारी ने कहा कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने और दर्ज विवरण को सही रखने में जनसहभागिता महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपील की कि यदि सूची में कोई त्रुटि मिले या निवास स्थान बदल गया हो, तो निर्धारित प्रपत्र में समय से आवेदन करें।

एसएसजे विवि में शोध और पाठ्यक्रमों को लेकर आरडीसी व बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक

के.के.पी संवाददाता

अल्मोड़ा। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा के कंप्यूटर विज्ञान विभाग में बुधवार को दो शोधार्थियों आशीष आर्या और ज्योति हरबोला की शोध उपाधि समिति (आरडीसी) की बैठक आयोजित की गई। इसके साथ ही कंप्यूटर विज्ञान विभाग के विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक भी हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ विभागाध्यक्ष डॉ. पारुल सक्सेना ने किया। आरडीसी की बैठक में दोनों शोधार्थियों के शोध कार्यों से जुड़े विभिन्न अकादमिक एवं शोधगत पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में संकायाध्यक्ष विज्ञान प्रो. जीसी शाह मौजूद रहे। बाह्य विशेषज्ञ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो. डीके लोबियाल और जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर के प्रो. एसडी सामंत रे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े, जबकि शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के प्रो. आरके श्रीवास्तव ने प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभाग किया। विशेषज्ञों ने शोध कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव और अकादमिक विचार प्रस्तुत किए। बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में एमसीए पाठ्यक्रम के प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2027-28 से बीसीए पाठ्यक्रम के प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर के शुल्क में उद्योग से जुड़ी कार्यशाला, संगोष्ठी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम मद में 1,500 रुपये की वृद्धि के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। विचार-विमर्श के बाद शुल्क वृद्धि को शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू करने के प्रस्ताव को संस्तुति प्रदान की गई। बैठक में एलएसएम परिसर पिथौरागढ़ के बीसीए के परिसर विभागाध्यक्ष डॉ. संतोष कुमार तथा कंप्यूटर विज्ञान विभाग, परिसर अल्मोड़ा के प्राध्यापक डॉ. मनोज कुमार बिष्ट, डॉ. सुशील चंद्र भट्ट, डॉ. सुमित खुल्बे, डॉ. अनामिका पंत, डॉ. अर्पिता जोशी, डॉ. पारस नेगी, ई. रवीन्द्र नाथ पाठक, तनुश्री ढौंढियाल, अनूप सिंह बिष्ट, कमल जोशी और नंदन सिंह कनवाल उपस्थित रहे। बैठक में शोधार्थियों के साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों ने भी प्रतिभाग किया।

ऑपरेशन प्रहार के तहत बागेश्वर पुलिस की कार्रवाई, 34 के खिलाफ चालान



के.के.पी संवाददाता

पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत पुलिस अधीक्षक बागेश्वर जितेन्द्र मेहरा (IPS) के निर्देशन में समाज में शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले और सार्वजनिक स्थलों पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ अभियान के क्रम में दिनाँक-24/11/2026 को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 17 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। जिसमें 02 वाहन का माननीय न्यायालय का चालान किया गया ।

पुलिस द्वारा देर सांय ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाते हुए होटल/ढाबों की चैकिंग की गयी पुलिस द्वारा बाहरी क्षेत्रों से आए अपराधी या संदिग्ध व्यक्ति जो अपनी पहचान छिपाकर या वेश बदलकर रह रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर लगातार चैकिंग की जा रही है । सार्वजनिक स्थानों में शान्ति व्यवस्था भंग करने, बिना पुलिस सत्यापन रह रहे 17 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस एक्ट में चलानी कार्यवाही की गयी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों को किया पुरस्कृत

के.के.पी संवाददाता

भिकियासैण(अल्मोड़ा)। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज चौनलिया में दानी देवी मेमोरियल ट्रस्ट ने स्वर्गीय रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित ब्लॉक स्तरीय वालीबाल प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत व विशिष्ट अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष भिकियासैण दीपक बिष्ट ने किया।जिसमें 10टीमों ने प्रतिभाग किया।

इस मौके पर हरीश रावत ने दानी देवी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से बीते वर्ष विद्यालय की 12वीं परीक्षा की छात्रा बबीता बिष्ट,दसवीं के यश बिष्ट को प्रथम पुरस्कार दिया गया। साथ आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम भूमिका नेगी, द्वितीय रिया पन्त ,तृतीय रोशन सिंह, जूनियर वर्ग प्रथम विक्रांत



कठायत, द्वितीय भारतीय रावत, तृतीय निधि को भी पुरस्कृत किया।

इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य नीम कड़ाकोटी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, दीपक कारगेती ,गंगा पंचोली, पूर्व प्रधानाचार्य मोहन सिंह बिष्ट, प्रधानाचार्य डॉ महेश दुर्गा पाल ,घनश्याम जोशी, भुवन भट्ट ,महावीर नेगी, संजय डैर्बी , हरीश मनराल जगत सिंह भंडारी आदि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से दीपिका ने बदली अपनी तकदीर, नौकरी तलाशने वाली बनीं दूसरों को रोजगार देने वाली उद्यमी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में स्वरोजगार को मिल रहा बढ़ावा, हल्द्वानी में मेकअप स्टूडियो स्थापित कर दीपिका ने रचा सफलता का नया अध्याय

के.के.पी संवाददाता

हल्द्वानी। हल्द्वानी निवासी दीपिका सनवाल ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया है। कभी बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना देखने वाली दीपिका को प्रतियोगी परीक्षाओं में अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने निराश होने के बजाय स्वरोजगार को अपना रास्ता बनाया और आज वह स्वयं उद्यमी बनने के साथ ही अन्य महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दीपिका ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, हल्द्वानी शाखा से 7 लाख रुपये की परियोजना के लिए ऋण प्राप्त किया। इसमें बैंक द्वारा 6.65 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया, जबकि 35 हजार रुपये का अंशदान दीपिका ने स्वयं किया। योजना के तहत उन्हें 1.05 लाख रुपये की सब्सिडी भी प्रदान की गई। दीपिका ने लैक्मे एकेडमी से

मातृ शक्ति गढ़ रही सफलता की कहानी



प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने कौशल को निखारा और हल्द्वानी में 'DEEPIKA SANWAL MAKEUP STUDIO' की शुरुआत की। शुरुआत में स्वयं के लिए रोजगार का अवसर तैयार करने वाली दीपिका ने धीरे-धीरे अपने व्यवसाय का विस्तार किया और अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर देने शुरू किए। आज उनके स्टूडियो में ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, फेशियल सहित विभिन्न ब्यूटी सेवाएं उपलब्ध हैं। उनके स्टूडियो से जुड़कर कई महिलाएं रोजगार प्राप्त कर रही हैं। बेहतर सेवाओं और गुणवत्तापूर्ण कार्य के चलते उनके व्यवसाय को पहचान मिली है तथा वर्तमान में उनका वार्षिक कारोबार लगभग 10 लाख रुपये तक पहुंच गया है। इस उद्यम से अब तक 5 लोगों को रोजगार मिला है। दीपिका की यह सफलता मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं को नौकरी तलाशने के बजाय अपना उद्यम शुरू करने और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की स्वरोजगारपरक योजनाएं युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

भीमताल विधानसभा की विभिन्न समस्याओं को लेकर दर्जा राज्यमंत्री भावना मेहरा ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

सड़को के सुधारीकरण की करी बात

के.के.पी संवाददाता

भीमताल। भीमताल विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान एवं विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से आवास सलाहकार परिषद की उपाध्यक्ष (दर्जा राज्यमंत्री) भावना मेहरा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की इस दौरान भावना मेहरा ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा उन्होंने भीमताल महायोजना के शीघ्र अनुमोदन विभिन्न प्रयोजनों के लिए चयनित भूमि एवं प्राधिकरण क्षेत्र में भवन निर्माण नियमों में व्यावहारिक छूट देते हुवे 100 वर्ग मीटर तक भवन निर्माण की अनुमति वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करने भू-उपयोग संबंधी विषयों के साथ ही विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न



सड़कों के सुधारीकरण एवं मरम्मत की मांग प्रमुखता से उठाई उन्होंने कहा कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र के नागरिक लंबे समय से इन समस्याओं के समाधान की अपेक्षा कर रहे हैं इन विषयों पर सकारात्मक कार्यवाही होने से स्थानीय जनता को राहत मिलेगी जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी भावना मेहरा ने मुख्यमंत्री से जनहित में उक्त समस्याओं के शीघ्र समाधान एवं संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया वहीं चाफी गोल्ज्यू मंदिर एवं मुक्तेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास से क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी जिससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने के स्थानीय लोगों की आजीविका के अवसर बढ़ेंगे।

28 नवंबर को सजेगा नैनीताल दुग्ध संघ का 77वां वार्षिक अधिवेशन, मुख्य अतिथि और अति विशिष्ट अतिथियों की रहेगी गरिमामयी मौजूदगी

के.के.पी संवाददाता

लालकुआं। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लालकुआं के 77वें वार्षिक सामान्य निकाय अधिवेशन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आगामी 28 नवंबर को हल्द्वानी के पीलीकोठी स्थित संकल्प वेंकट हॉल में आयोजित होने वाले इस महत्वपूर्ण अधिवेशन में मुख्य अतिथि एवं अति विशिष्ट अतिथियों सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, सहकारिता क्षेत्र से जुड़े गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादक प्रतिभाग करेंगे। दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा की अध्यक्षता में संचालक मंडल के सदस्यों एवं अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में वार्षिक अधिवेशन के आयोजन स्थल, कार्यक्रम की रूपरेखा और



व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। विचार-विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से अधिवेशन के आयोजन पर मुहर लगा दी गई। वार्षिक सामान्य निकाय अधिवेशन में दुग्ध संघ की वर्षभर की गतिविधियों, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, आय-व्यय के विवरण तथा दुग्ध उत्पादकों के हितों से जुड़ी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने, उत्पादकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और सहकारी व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषय भी अधिवेशन के केंद्र में रहेंगे। 28 नवंबर को आयोजित होने वाले इस भव्य अधिवेशन में मुख्य अतिथि एवं अति विशिष्ट अतिथियों के साथ जनप्रतिनिधियों, सहकारिता क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों और गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी मौजूदगी रहेगी। कार्यक्रम में संघ की उपलब्धियों को साझा करने के साथ ही दुग्ध उत्पादकों के योगदान को सम्मान देने और सहकारी आंदोलन को नई मजबूती प्रदान करने से जुड़े विषय विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बैठक में संचालक मंडल सदस्य गोविंद सिंह मेहता, कृष्ण कुमार, आनंद सिंह नेगी, पुष्पा देवी, खष्टी देवी, दीपा देवी, हेमा देवी, दीपा देवी रैक्वाल एवं थान सिंह बिष्ट मौजूद रहे। इसके अलावा दुग्ध संघ के सामान्य प्रबंधक अनुराग शर्मा, वित्त प्रभारी उमेश पठालनी, प्रशासन एवं विपणन प्रभारी संजय सिंह भाकुनी, पी एंड आई प्रभारी सुभाष बाबू, खलील अहमद सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर है, आत्मज्ञान से मिलेगी सच्ची मुक्ति : MAAsterG

मसूरी से हरिद्वार लौटे आध्यात्मिक गुरु, 80 शिष्यों के साथ पूरी की नौ दिवसीय मुक्ति यात्रा

के.के.पी संवाददाता

हरिद्वार। बढ़ते तनाव, चिंता, अकेलेपन और भावनात्मक चुनौतियों के बीच आध्यात्मिक गुरु MAAsterG ने युवाओं को आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की राह दिखाने का संदेश दिया। 80 शिष्यों के साथ 15 से 24 नवंबर तक चली नौ दिवसीय 'जीएच मुक्ति यात्रा-आत्मज्ञान की यात्रा' के बाद वह हरिद्वार लौटे। यात्रा के दौरान मसूरी और हरिद्वार में आध्यात्मिक गतिविधियों के माध्यम से जीवन के गहरे उद्देश्य और स्वयं को समझने पर जोर दिया गया।

MAAsterG ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर जागृति और आत्मबोध की संभावना

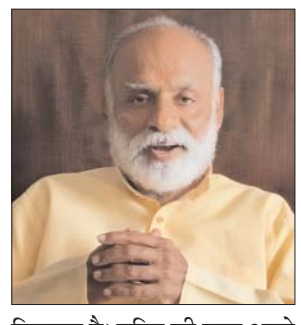

विद्यमान है। मुक्ति की यात्रा अपने वास्तविक स्वरूप को जानने, जीवन के गहरे उद्देश्य को समझने और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की यात्रा है। उन्होंने कहा कि भारत को फिर से विश्वगुरु के स्थान पर स्थापित करने की शुरुआत बाहरी बदलाव से नहीं, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक परिवर्तन से होगी।

उन्होंने बताया कि नवंबर 2007 में इन्हीं स्थानों पर उन्हें गहन आध्यात्मिक जागृति का अनुभव हुआ था। उस अनुभव के सार को वह पिछले कई वर्षों से अपने शिष्यों के साथ साझा कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि आध्यात्मिक चेतना का यह वातावरण केवल मसूरी और हरिद्वार तक सीमित न रहे, बल्कि देश और दुनिया के लोगों तक पहुंचे।

MAAsterG ने कहा कि उनके मिशन का एक प्रमुख केंद्र आज का युवा वर्ग है। युवाओं में बढ़ते अकेलेपन, तनाव, चिंता, अवसाद, नींद संबंधी समस्याओं और भावनात्मक चुनौतियों को लेकर उन्होंने चिंता जताई। उनका मानना है कि भारत का भविष्य युवाओं के आंतरिक कल्याण पर निर्भर करता है।

उन्होंने बताया कि पिछले 19 वर्षों में उन्होंने बिना किसी सामाजिक माध्यम मंच का उपयोग किए लाखों लोगों से व्यक्तिगत संवाद के जरिए अपने अनुभव साझा किए। दिसंबर 2023 में उन्होंने सार्वजनिक मंचों और सामाजिक माध्यमों के जरिए 'मिशन 800 करोड़' की शुरुआत की। इसका उद्देश्य आध्यात्मिक संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि चार पीढ़ियों के लोग उनके साथ जुड़कर जीवन को आनंद और उत्सव के रूप में जीने का अनुभव कर रहे हैं।

आर्मी पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों को करियर और छात्रवृत्ति के अवसरों की दी जानकारी

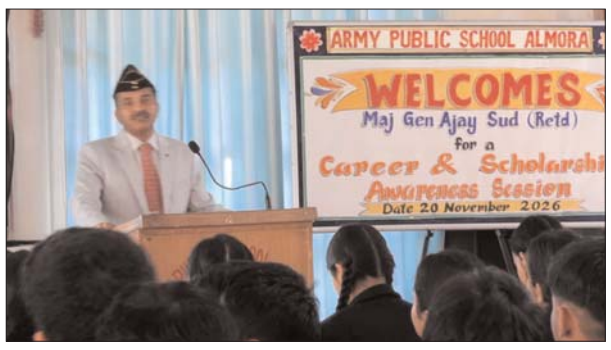

के.के.पी संवाददाता

अल्मोड़ा। आर्मी पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को करियर, छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा के अवसरों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। सत्र में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त मेजर जनरल अजय सूद ने विद्यार्थियों को सेना में उच्च पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया के साथ भविष्य में आगे बढ़ने के विभिन्न अवसरों की जानकारी दी। मेजर जनरल अजय सूद ने विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने सेना सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों और उनके लिए आवश्यक तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। सत्र के दौरान विद्यालय के शिक्षक भी मौजूद रहे और विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त की। प्रधानाचार्य सुशील जोशी ने बताया कि विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्यालय में इस प्रकार के जागरूकता सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय परिवार विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ब्रह्मानंद सरस्वती का उल्लेखनीय योगदान : मंकाल एस वैद्य

साधना कुटीर के दशम वार्षिकोत्सव में संत–महात्माओं और जनप्रतिनिधियों ने की सराहना

के.के.पी संवाददाता

हरिद्वार। भूपतवाला स्थित श्यामलोक कॉलोनी में साधना, सेवा और संस्कार का संगम देखने को मिला। श्रीराम क्षेत्र महासंस्थान, नित्यनंद नगर, धर्मस्थल, कर्नाटक की ओर से आयोजित 'साधना कुटीर' के दशम वार्षिकोत्सव में संत-महात्माओं, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों से आए गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। महामंडलेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में संकीर्तन के बाद संतों ने श्रद्धालुओं को आशीर्वचन दिए।

महामंडलेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ने कहा कि संत का उद्देश्य धन-संपत्ति जुटाना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सुख, शांति और सद्भाव का मार्ग दिखाना है। सनातन धर्म हमें परोपकार, सेवा, त्याग और मानव कल्याण की शिक्षा देता है। संत का जीवन





लोककल्याण के लिए समर्पित होता है। पैसा इकट्ठा करना हमारा काम नहीं है, बल्कि मां भगवती लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। जब व्यक्ति सच्चे मन से मां लक्ष्मी की आराधना करता है तो जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता का मार्ग प्रशस्त होता है। श्रीमहंत प्रेमानंद गिरि महाराज ने कहा कि संत समाज सदैव मानव सेवा, संस्कार और सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए समर्पित रहा है। साधना केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा करना भी सच्ची साधना है। उन्होंने कहा कि महामंडलेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती कर्नाटक में रहकर पिछले कई वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। साधना कुटीर के माध्यम से आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ सेवा कार्यों को भी निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने युवाओं को संस्कार और सनातन संस्कृति से जोड़ने का आह्वान करते हुए साधना कुटीर के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

कर्नाटक विधानसभा उपाध्यक्ष मंकाल एस वैद्य ने कहा कि संतों के मार्गदर्शन में समाज सेवा के कार्यों को नई गति मिलती है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

पूर्व सांसद एवं भाजपा कर्नाटक के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि संतों के सानिध्य से समाज को नई दिशा और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। कर्नाटक से आए अतिथियों ने हरिद्वार की आध्यात्मिक परंपरा की भी सराहना की।

कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमहंत प्रेम गिरि महाराज ने की, जबकि संचालन श्रीमहंत देवानंद सरस्वती ने किया। इस दौरान श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अध्यक्ष श्रीमहंत मोहन भारती, अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमहंत विद्यानंद सरस्वती, महामंत्री श्रीमहंत महेशपुरी, महामंडलेश्वर स्वामी अनंत चैतन्य सरस्वती, महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरि, महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतानानंद, श्रीमहंत इन्द्रानंद सरस्वती, महंत मायावानंद सरस्वती, स्वामी उमाशंकर महाराज, स्वामी धीरेंद्र पुरी महाराज सहित बड़ी संख्या में संत-महात्मा मौजूद रहे।

विशेष उपस्थिति में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, विधायक गुरुराज गंटीहोल, विधायक हरीश पुंजा, कर्नाटक विद्युत आपूर्ति बोर्ड के अध्यक्ष हरीश कुमार, जयशंकर विश्वनाथन, रक्षित शिवराम, हरीश पुजारी, उद्योगपति किरण चंद्र पुष्पागिरी और पार्षद किरण कुमार कोडिकल,नरेंद्र पाटीदार, डॉ प्रभात,देवेंद्र पंत ,सावन कुमार,सहित कई गणमान्य लोग शामिल रहे।

हरिद्वार नगर सीट पर संत की सियासी दस्तक, श्रीमहंत राज गिरि ने ठोकी दावेदारी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात कर मांगा टिकट, विकास और सनातन परंपरा को बताया प्राथमिकता

के.के.पी संवाददाता

हरिद्वार। विधानसभा चुनाव की आहट के साथ धर्मनगरी हरिद्वार की सियासत में संत समाज की सक्रियता बढ़ने लगी है। हरिद्वार नगर विधानसभा सीट से अब संत समाज की ओर से भी दावेदारी सामने आ गई है। श्रवण नाथ मठ के सचिव, ऋषिकेश स्थित वीरभद्र महादेव मंदिर के प्रबंधक और वीरपुर मठ के अध्यक्ष श्रीमहंत राज गिरी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट से मुलाकात कर हरिद्वार नगर सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। महंत की दावेदारी सामने आने के बाद भाजपा के भीतर और स्थानीय राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हरिद्वार नगर विधानसभा सीट भाजपा के लिए लंबे समय से मजबूत गढ़ मानी जाती है। वर्ष 2002 में हुए पहले विधानसभा





चुनाव के बाद से भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक लगातार पांच बार इस सीट से विधायक चुने गए हैं। ऐसे में धार्मिक क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाले महंत राज गिरी की ओर से टिकट की दावेदारी किए जाने को आगामी चुनाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

कुंभ और हरिद्वार के विकास पर चर्चा

महंत राज गिरी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात के दौरान हरिद्वार के समग्र विकास, आगामी कुंभ की तैयारियों और तीर्थनगरी की धार्मिक मर्यादा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हरिद्वार विश्वभर में सनातन संस्कृति और आस्था का प्रमुख केंद्र है। संत समाज की सक्रिय भागीदारी से धर्मनगरी के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को नई दिशा दी जा सकती है।

धार्मिक क्षेत्र में निभा रहे जिम्मेदारी

महंत राज गिरी हरिद्वार और ऋषिकेश के धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। वह श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी और ऐतिहासिक श्रवण नाथ मठ के सचिव हैं। इसके अलावा ऋषिकेश स्थित प्राचीन वीरभद्र महादेव मंदिर के प्रबंधक और वीरपुर मठ के अध्यक्ष के रूप में भी धार्मिक, शैक्षणिक और जनसेवा से जुड़े कार्यों में भूमिका निभा रहे हैं। उनकी चुनावी दावेदारी के बाद हरिद्वार नगर सीट पर भाजपा के संभावित प्रत्याशियों को लेकर सियासी चर्चाएं और तेज हो गई हैं।

'ऑपरेशन भल छौ' से सामुदायिक पुलिसिंग को धरातल पर मजबूत करती बागेश्वर पुलिस; बुजुर्गों की जानी कुशलक्षेम, नशे के दुष्प्रभावों व साइबर अपराध से किया जागरूक

के.के.पी संवाददाता

पुलिस अधीक्षक बागेश्वर जितेन्द्र मेहरा (IPS) के कुशल निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा नागरिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल साक्षरता एवं अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु व्यापक स्तर पर सामुदायिक पुलिसिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कोतवाली बागेश्वर पुलिस द्वारा क्षेत्र में विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया गया।

अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बागेश्वर अनिल उपाध्याय ने पुलिस टीम के साथ गांवों में अकेले निवास कर रहे बुजुर्गों व वरिष्ठ नागरिकों से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर उनका हाल-चाल जाना। पुलिस टीम ने उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी समस्याओं की जानकारी लेते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि किसी भी आकस्मिक संकट, बीमारी या आपातकालीन आवश्यकता के समय बागेश्वर पुलिस उनकी सेवा और सहायता के लिए 24 घंटे तत्पर है।

महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उपस्थित महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों तथा घरेलू हिंसा के विरुद्ध बने कड़े कानूनों की जानकारी दी गई। साथ ही महिला हेल्पलाइन 1090 एवं राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर डायल 112 की उपयोगिता समझाई गई।

वर्तमान डिजिटल युग में वरिष्ठ नागरिकों व आमजन को निशाना बना रहे साइबर अपराधियों के प्रति सचेत करते हुए 'डिजिटल अरेस्ट', ऑनलाइन लॉटरी फ्रॉड, फर्जी बिजली बिल मैसेज तथा बैंक अधिकारी बनकर आने वाली फर्जी कॉल्स के खतरों से आगाह किया गया। सभी को अपनी गोपनीय बैंकिंग जानकारी (OTP/PIN) साझा न करने की सख्त हिदायत दी गई तथा ठगी होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई।

समाज व युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने हेतु जागरूक करते हुए आमजन से अपील की गई कि वे अपने आस-पास होने वाली नशा तस्करी संबंधी सूचना तत्काल मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 या नजदीकी पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

संपादकीय

सत्ता की राजनीति में धर्म, सनातन और भारतीय संस्कृति पर असर

धर्म आस्था, विश्वास और नैतिकता का विषय है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल सत्ता हासिल करने और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए होने लगता है, तो नुकसान केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था का नहीं, बल्कि उस धर्म और संस्कृति का भी होता है, जिसके नाम पर राजनीति की जाती है। भारत में पिछले तीन दशकों से धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति ने इसी तरह की परिस्थितियां पैदा की हैं। आजादी के बाद भारतीय संविधान लागू होने से लेकर 1990 तक भारतीय राजनीति में लोकतांत्रिक परंपराओं, संवैधानिक मूल्यों और कानून के शासन को प्रमुखता देने की कोशिश हुई। हालांकि उस दौर में भी धार्मिक और सामुदायिक विवाद होते रहे, लेकिन 1990 के बाद धर्म को चुनावी राजनीति का प्रभावशाली हथियार बनाने का सिलसिला तेजी से बढ़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि धार्मिक आस्था और राजनीतिक विचारधारा के बीच की दूरी लगातार कम होती चली गई। सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि धर्म की रक्षा का दावा करने वाले कुछ लोग, आज धर्म की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं। रामदेव, आसाराम, राम रहीम और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जैसे अलग-अलग पहचान रखने वाले चर्चित बाबाओं के अपराधिक कृत्य ओर समय-समय पर विवाद सामने आते रहे हैं। किसी पर कानूनी आरोप लगे, किसी के बयान विवादों में रहे, किसी की धार्मिक गतिविधियों को लेकर सवाल उठे। ऐसे मामलों ने आम श्रद्धालुओं के मन में यह सवाल पैदा किया है कि धर्म के नाम पर स्थापित होने वाली व्यवस्थाओं का वास्तविक उद्देश्य क्या है?

हाल के दिनों में बाबा रामदेव और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बीच सामने आए वैचारिक मतभेदों और बयानों ने इस बहस को और तेज कर दिया है। सवाल यह है कि क्या धार्मिक मंचों पर एक-दूसरे को चुनौती देने, पाखंडी बताने और भगवान राम तथा कृष्ण के नाम का सहारा लेकर अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश से सनातन धर्म मजबूत होगा? भगवान राम और कृष्ण भारतीय संस्कृति के आदर्श हैं। उन्हें किसी बाबा, राजनीतिक दल या चुनावी रणनीति की प्रतिस्पर्धा का माध्यम बनाना करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। धर्म के नाम पर चढ़ावे, दान और मंदिरों की संपत्ति को लेकर उठने वाले विवाद भी कम गंभीर नहीं हैं। मंदिरों में चोरी, धार्मिक संस्थाओं के धन के दुरुपयोग के आरोप और धार्मिक नेतृत्व के बीच संपत्ति तथा प्रभाव को लेकर संघर्ष की खबरें आस्था की बुनियाद को कमजोर करती हैं। जब धर्म के नाम पर लोगों से धन जुटाया जाता है, उसी धन को लेकर धर्म के ठेकेदारों के बीच विवाद पैदा होते हैं। तब श्रद्धालुओं का विश्वास स्वाभाविक रूप से प्रभावित होता है। धर्म- सेवा, त्याग और परोपकार का माध्यम होना चाहिए, न कि आर्थिक लाभ और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का। इस पूरी परिस्थिति का राजनीतिक पक्ष भी समझना जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में हिंदुत्व और धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर जो राजनीतिक एकजुटता दिखाई देती थी, उसके भीतर अब वैचारिक और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के संकेत उभर रहे हैं। अलग-अलग धार्मिक संगठनों, बाबाओं और राजनीतिक समर्थकों के बीच बढ़ते मतभेद इस एकजुटता को प्रभावित कर रहे हैं। हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रदर्शन हुए हैं, उसमें जो नई पीढ़ी है उसने धार्मिक प्रतिबद्धता से हटकर जिस तरह अपनी बात रखी है। जिस धार्मिक भावना को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया, वही अब बड़े टकराव का कारण बनती दिखाई दे रही है।

राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कुछ समय के लिए चुनावी लाभ दे सकता है। इसके दीर्घकालीन परिणाम समाज और संस्कृति के लिए नुकसानदायक होते हैं। इतिहास बताता है, धर्म की वास्तविक शक्ति सत्ता के संरक्षण में नहीं, बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों, विश्वास और मानवीय व्यवहार में निहित होती है। आज आवश्यकता इस बात की है, हिंदू समाज बाबाओं के विवादों और राजनीतिक नारों से ऊपर उठकर अपने धर्म के मूल सिद्धांतों को समझे। मंदिरों की संपत्ति की पारदर्शिता सुनिश्चित हो, धार्मिक संस्थाओं की जवाबदेही तय हो। कानून से ऊपर किसी को भी न माना जाए। सनातन धर्म की रक्षा किसी राजनीतिक दल या बाबाओं से नहीं आती है, बल्कि उसकी उदारता, सहिष्णुता, सत्य, सेवा और समरसता की परंपरा से धार्मिक आस्था और संगठन मजबूत होते हैं।

हमारी लोकतांत्रिक आत्मा का जीवंत घोषणापत्र है संविधान

योगेश कुमार गोयल

- भारतीय गणतंत्र की आत्मा संविधान के 77 वर्षों का गौरव

विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है, जो वैसे तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था लेकिन इसे 26 नवम्बर 1949 को ही स्वीकृत कर लिया गया था। इसी दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए 26 नवम्बर का दिन ही 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस दिन संविधान निर्माता के रूप में डा. भीमराव अम्बेडकर को याद किया जाता है, जिन्होंने दुनिया के सभी संविधानों को परखने के बाद भारतीय संविधान के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार किया। भारत का संविधान ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है और साथ ही हमारे कर्त्तव्यों को भी निर्धारित करता है। संविधान सभा को इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का लंबा समय लगा था। वर्ष 2015 में पहली बार निर्णय लिया गया कि संविधान सभा की निर्मात्री समिति के अध्यक्ष डा. भीमराव अम्बेडकर के 125वें जयंती वर्ष के अवसर पर 26 नवम्बर 2015 को संविधान दिवस मनाया जाए और तभी से यह दिवस मनाए जाने की परम्परा शुरू हुई। यह दिवस मनाए जाने का उद्देश्य देश के नागरिकों को संविधान के प्रति सचेत करना, समाज में संविधान के महत्व का प्रसार करना तथा डा. भीमराव अम्बेडकर के अमूल्य योगदान और उनके विचारों, आदर्शों का स्मरण करना है।

भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष के तौर पर डा. भीमराव अम्बेडकर की नियुक्ति की गई। पं. जवाहरलाल नेहरू, डा राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद इत्यादि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डा राजेन्द्र प्रसाद थे और नियमानुसार संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर भी उन्हीं के होने चाहिएं थे किन्तु पं. नेहरू ने संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। संविधान का मसौदा तैयार करने में किसी भी प्रकार की टाइपिंग अथवा प्रिंटिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, तभी से हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। संविधान लागू होने से दो दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान की तीनों प्रतियों पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे। 9 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में पहली बार समवेत हुई थी लेकिन मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग को लेकर इस बैठक का बहिष्कार किया था। 11 दिसम्बर 1946 को हुई संविधान सभा की बैठक में डा. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और वे संविधान के निर्माण का कार्य पूरा होने तक इस पद पर रहे।

संविधान गौरव दिवस : राष्ट्र की गरिमा, नागरिक अधिकार और कर्तव्य का संकल्प

सुरेन्द्र शर्मा

26 नवंबर भारतीय लोकतंत्र की गौरवशाली तिथि है। इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया। इसके अधिकांश प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुए और भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बना। संविधान दिवस हमें स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का स्मरण कराता है। यह नागरिक अधिकारों को समझने तथा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का संकल्प लेने का अवसर है।

स्वतंत्रता के समय हमारा देश विभाजन की त्रासदी, सामाजिक विषमता, आर्थिक अभाव और निरक्षरता जैसी चुनौतियों से जूझ रहा था। ऐसी परिस्थितियों में संविधान निर्माताओं ने न्याय, समानता और लोकतंत्र पर आधारित व्यवस्था चुनी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव आंबेडकर सहित अनेक सदस्यों ने चर्चा, संशोधन और सहमति से संविधान निर्माण की ऐतिहासिक जिम्मेदारी पूरी की। विभिन्न विचारों और अनुभवों का यह समन्वय लोकतांत्रिक संवाद की शक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण है।

संविधान के निर्माण में बाबासाहेब भीमराव रामजी आंबेडकर का योगदान विशेष रूप से वंदनीय है। सामाजिक भेदभाव की पीड़ा से परिचित होने के कारण व्यक्ति की गरिमा, समान अवसर और वंचितों के अधिकार उनके चिंतन के केंद्र में रहे। बाबा साहेब के प्रति सच्ची श्रद्धा तभी होगी, जब हम अपने व्यवहार से छुआछूत, जातिगत अहंकार और सामाजिक अपमान दूर करेंगे। शिक्षा और लोकतांत्रिक प्रयासों से परिवर्तन लाने का उनका संदेश आज भी प्रेरक है।

संविधान की प्रस्तावना का आरंभ 'हम, भारत के लोग' से होता है। ये शब्द बताते हैं कि संवैधानिक सत्ता का मूल स्रोत जनता है। प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प व्यक्त करती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता इसके प्रमुख आदर्श हैं। बंधुता व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने की प्रेरणा देती है।

भारतीय लोकतंत्र की शक्ति जागरूक नागरिक हैं। मतदान देश की दिशा निर्धारित करने में हमारी भागीदारी है, इसलिए निर्णय जानकारी, विवेक और सार्वजनिक हित के आधार पर होना चाहिए।

मौलिक अधिकार सम्मानपूर्ण जीवन का आधार हैं। इनका वास्तविक महत्व तब दिखाई देता है, जब कमजोर व्यक्ति भी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सके और न्याय प्राप्त कर सके। असहमति लोकतांत्रिक संवाद का स्वाभाविक अंग है; आलोचना को शत्रुता में बदलने से सामाजिक विश्वास कमजोर होता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की गरिमा के साथ उनकी जवाबदेही भी आवश्यक है। सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का आचरण पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए यह शिक्षा हमें संविधान ने दी है।

नागरिक कर्तव्यों में संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, देश की एकता की रक्षा, सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा शामिल हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना भी समाज को आगे बढ़ाते हैं। हमारी भाषाओं, आस्थाओं और परंपराओं की विविधता राष्ट्रीय संपदा है। किसी की पहचान के आधार पर अपमान या घृणा फैलाना इस साझा विरासत को चोट पहुँचाता है।

वर्ष 2015 में भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान की भावना को 'Dignity For Indian and Unity for India' अर्थात प्रत्येक भारतीय की गरिमा और भारत की एकता से जोड़ा है। उनके अनुसार अधिकारों और कर्तव्यों का अटूट संबंध है। यातायात नियमों का पालन, जल संरक्षण और समय पर कर भुगतान जैसे दैनिक कार्यों में भी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी प्रकट होती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान को वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक बताते हुए विकसित भारत के निर्माण पर बल दिया है। उन्होंने सामान्य पृष्ठभूमि के नागरिकों को आगे बढ़ने की शक्ति देने में संविधान की भूमिका रेखांकित की। पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं का सम्मान करने का उनका सुझाव नई पीढ़ी में लोकतांत्रिक भागीदारी और दायित्व की भावना बढ़ाने का अवसर है।

संविधान का गौरव मनाते समय उसके उल्लंघन के इतिहास से सीखना भी आवश्यक है। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाया गया 1975 का आपातकाल नागरिक स्वतंत्रताओं पर गंभीर प्रहार था। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियाँ, प्रेस पर सेंसरशिप और कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन पर प्रतिबंध सत्ता के केंद्रीकरण के खतरों की चेतावनी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन घटनाओं के संदर्भ में कांग्रेस पर संवैधानिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक स्वार्थ के लिए कमजोर करने वाला बताया है।

आपातकाल के दौरान 39वें संशोधन से इंदिरा गांधी के चुनाव को विशेष संरक्षण देने वाले प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक ठहराया। 42वें संशोधन द्वारा संसद की संशोधन शक्ति को असीमित करने और संविधान संशोधनों की न्यायिक समीक्षा रोकने के प्रयास भी हुए। 'मिनर्वा मिल्स' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित प्रावधान निरस्त किए।

कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय 2005 में बिहार विधानसभा का विघटन भी असंवैधानिक घोषित हुआ। ये घटनाएँ बताती हैं कि संवैधानिक सीमाओं का पालन प्रत्येक सरकार के लिए अनिवार्य है।

संविधान गौरव दिवस मनाना तभी सार्थक होगा, जब संविधान का सम्मान हमारे आचरण, और सार्वजनिक जीवन में दिखाई दे।

7 जून 2024 को नई दिल्ली स्थित संविधान सदन, अर्थात पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय संविधान की प्रति के समक्ष शीश झुकाया और उसे उठाकर श्रद्धापूर्वक अपने माथे से लगाया था लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया के बीच हुआ यह क्षण संविधान के प्रति सम्मान की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति था।

इस दृश्य का संदेश गहरा है– लोकतंत्र में प्रत्येक पद की गरिमा संविधान से आती है और उसके साथ जनता के प्रति उत्तरदायित्व भी जुड़ा होता है। संविधान को नमन करना उसके निर्माताओं की दूरदृष्टि, स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष तथा देशवासियों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के प्रति आदर प्रकट करना है।

संविधान का सम्मान तभी सार्थक होता है, जब उसके आदर्श हमारे आचरण में दिखाई दें। प्रधानमंत्री जी का यह भावपूर्ण नमन हमें इसी संकल्प की प्रेरणा देता है।

संविधान का सम्मान जेब में किताब रखने से नहीं, उसके आदर्शों पर चलने से होता है

संविधान की पुस्तक साथ रखना अच्छी बात है। लेकिन जो लोग इसे लेकर घूमते हैं, उनसे देश यह अपेक्षा भी करता है कि उनके व्यवहार, निर्णय और सार्वजनिक जीवन में संवैधानिक मूल्यों का सम्मान दिखाई दे। संविधान के प्रति निष्ठा का प्रमाण केवल उसकी प्रति दिखाने से नहीं मिलता; वह अपने आचरण से देना पड़ता है। भारत का संविधान किसी एक दल, परिवार या विचारधारा की संपत्ति नहीं है। यह स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों, संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि और करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं का साझा दस्तावेज है। इसलिए इसे राजनीतिक मंच पर उठाने वाले हर व्यक्ति को उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए।

संविधान अधिकार देता है, तो कर्तव्य का बोध भी कराता है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की शक्ति है। सरकार से प्रश्न पूछना, नीतियों की आलोचना करना और शांतिपूर्ण विरोध करना लोकतांत्रिक जीवन के आवश्यक अंग हैं। लेकिन इसी स्वतंत्रता के साथ तथ्यों के प्रति ईमानदारी, दूसरों की गरिमा का सम्मान और सार्वजनिक शांति की जिम्मेदारी भी जुड़ी है। अपने लिए स्वतंत्रता माँगते हुए विरोधी की आवाज दबाना संवैधानिक भावना के अनुरूप कैसे हो सकता है?

इसी तरह, समानता की बात करने वालों को अपने संगठन और व्यवहार में भी समान अवसर देने चाहिए। सामाजिक न्याय का दावा तभी विश्वसनीय बनता है, जब वंचित व्यक्ति को सम्मान, प्रतिनिधित्व और आगे बढ़ने का वास्तविक अवसर मिले। संविधान का नाम लेकर समाज में अविश्वास बढ़ाने से उसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती।

संवैधानिक नैतिकता ही लोकतंत्र की मजबूती का आधार

राज कुमार सिन्हा

लोकतंत्र का मूल आधार यह है कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम करेगी। संविधान केवल शासन चलाने वाला एक दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, नागरिकों के अधिकारों, संस्थाओं की स्वतंत्रता और सरकार की जवाबदेही का आधार है। भारत में जब कोई नेता मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभालता है, तो वह संविधान के प्रति निष्ठा और कानून के अनुसार काम करने की शपथ लेता है। इस शपथ का उद्देश्य देश के प्रति निष्ठा, जनता के हितों की रक्षा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना है। लेकिन जब शपथ लेने के बाद राजनीतिक लाभ, सत्ता में बने रहने और व्यक्तिगत या पार्टी हितों को प्राथमिकता दी जाने लगती है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या संविधान की शपथ अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा कर रही है।भारतीय राजनीति में ऐसे अनेक प्रसंग सामने आते रहे हैं, जिनमें संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या, राजनीतिक दलों के बीच जोड़-तोड़ और सत्ता परिवर्तन को लेकर विवाद पैदा हुए हैं। इन घटनाओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मर्यादाओं और राजनीतिक नैतिकता पर गंभीर बहस को जन्म दिया है।

भारत में कई बार देखा गया है कि शपथ लेने के बाद नेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए पाला बदल लेते हैं। चुनाव के समय जनता किसी राजनीतिक दल या उसके उम्मीदवार को समर्थन देती है, लेकिन चुनाव के बाद राजनीतिक समीकरण बदलने से सरकारों की स्थिरता प्रभावित होने लगती है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दलबदल विरोधी कानून बनाया गया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के अवसरवादी दलबदल पर रोक लगाना और लोकतांत्रिक जनादेश की रक्षा करना था। हालांकि, इस कानून के बावजूद इसके प्रावधानों की व्याख्या, राजनीतिक दलों के विलय, विधायकों की अयोग्यता और निर्णय लेने में होने वाली देरी को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। कई बार इन प्रक्रियागत जटिलताओं का लाभ उठाकर सरकारें गिराने और नई सरकारें बनाने की कोशिशें होती हैं। इससे लोकतंत्र में जनता के जनादेश और निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही को लेकर प्रश्न उठते हैं। यह समझना आवश्यक है कि राजनीतिक दल बदलना या सरकार बनाना अपने आप में हमेशा असंवैधानिक नहीं होता। संविधान और कानून के अंतर्गत राजनीतिक परिवर्तन की गुंजाइश है। लेकिन जब इन प्रावधानों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक जनादेश को कमजोर करने या सत्ता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तब संवैधानिक नैतिकता का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। कानून का उद्देश्य केवल तकनीकी प्रक्रियाओं का पालन करना नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना की रक्षा करना भी है। संविधान की शपथ लेने वाले नेताओं और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। लेकिन यदि कोई चुनी हुई सरकार या राज्यपाल जानबूझकर संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करता है, तो राज्य में संवैधानिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर संकट पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, विधेयकों पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी, विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने को लेकर विवाद या सरकार गठन की प्रक्रिया में संवैधानिक परंपराओं की अलग-अलग व्याख्याएं संस्थाओं के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर सकती हैं। ऐसे मामलों में समयबद्ध निर्णय, स्पष्ट संवैधानिक मानदंड और निष्पक्ष प्रक्रिया लोकतंत्र की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक हैं।

राज्यपाल का पद संवैधानिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक पक्षधरता से ऊपर उठकर अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करें। इसी तरह निर्वाचित सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी शक्तियों का उपयोग संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर करें। किसी भी संस्था को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इस प्रकार नहीं करना चाहिए, जिससे दूसरी संवैधानिक संस्था की भूमिका या लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हो। जब कार्यपालिका या विधायिका संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ती है अथवा उन पर उल्लंघन के गंभीर आरोप लगते हैं, तो न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। न्यायिक हस्तक्षेप संवैधानिक विवादों का समाधान करने और कानून के शासन को बनाए रखने का माध्यम है। हालांकि, संस्थाओं के बीच बार-बार टकराव की स्थिति यह भी दर्शाती है कि संवैधानिक प्रक्रियाओं के पालन और संस्थागत संवाद को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। संविधान की शपथ का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में कानून का शासन स्थापित रहे। कानून का शासन अर्थात शासन किसी व्यक्ति की इच्छा, राजनीतिक प्रभाव या व्यक्तिगत हितों के आधार पर नहीं, बल्कि संविधान और कानून के अनुसार संचालित हो। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति या संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। जब राजनीतिक नेतृत्व अपने पद और शक्तियों का उपयोग संवैधानिक सीमाओं से परे जाकर करने लगता है, तो कानून के शासन की अवधारणा कमजोर पड़ने का खतरा पैदा होता है। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति केंद्रित राजनीति को बढ़ावा मिलता है, जिसमें संस्थागत नियमों की तुलना में किसी नेता या राजनीतिक दल की इच्छा अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

इसका प्रभाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहता है। प्रशासनिक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और समाज के अन्य वर्गों पर भी इसका असर पड़ता है। जब शीर्ष स्तर पर नियमों के पालन को लेकर दोहरे मानदंड दिखाई देता है, तो सामान्य नागरिकों के मन में यह धारणा मजबूत होती है कि नियमों का पालन सभी के लिए समान रूप से आवश्यक नहीं है। इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक आचरण की संस्कृति प्रभावित होती है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं की अपनी-अपनी संवैधानिक या कानूनी भूमिका है। इन संस्थाओं की विश्वसनीयता उनके निष्पक्ष कामकाज, पारदर्शिता और कानून के अनुरूप निर्णय लेने पर निर्भर करती है। जब इन संस्थाओं के कामकाज को लेकर राजनीतिक पक्षपात के आरोप सामने आते हैं, तो उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सार्वजनिक बहस शुरू हो जाती है।

चुनावी महासंग्राम की राह पर उत्तर प्रदेश

निर्मल रानी

उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सदस्यों के लिये होने वाले आम चुनाव, फ़रवरी-मार्च 2027 में होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के 4 अन्य राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी संभवतः फ़रवरी-मार्च 2027 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इन सभी पाँचों राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च से मई 2027 के बीच समाप्त हो रहा है। इन पांच राज्यों के अलावा, वर्ष 2027 के अंत यानी नवंबर-दिसंबर में दो अन्य राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव निर्धारित हैं। इन विधान सभा चुनावों को 2029 के प्रस्तावित लोकसभा चुनावों के सेमी फ़ाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। वैसे तो इन सभी पांचों राज्यों में चुनाव बेहद दिलचस्प होने की संभावना है परन्तु सबसे चुनौतीपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार अपनी चुनावी बिसात बिछाने वाला देश का यह सबसे बड़ा प्रदेश इस बार न केवल साम्प्रदायिक बल्कि जातीय समीकरणों में भी बुरी तरह उलझ चुका है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एस आई आर के बाद, निर्वाचन आयोग ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ड्राफ़्ट मतदाता सूची जारी कर दी है और नाम जोड़ने व सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 17 नवंबर 2026 को जारी ड्राफ़्ट मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश में कुल 13.58 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए हैं। 10 अप्रैल 2026 को एसआईआर के बाद प्रकाशित अंतिम सूची की तुलना में इस मसौदा सूची में 18,84,113 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में महिला मतदाताओं की संख्या में 10,96,828 और पुरुष मतदाताओं की संख्या में 7,87,449 का इज़ाफ़ा हुआ है। इससे पहले एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 15.44 करोड़ मतदाताओं की जांच के बाद 12.55 करोड़ नाम बरक़रार रखे गए थे और लगभग 2.89 करोड़ नाम सूची से हटाए गए थे। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि पंचायत और विधानसभा मतदाता सूची के भ्रम के कारण 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम सूची में नहीं जुड़ पाए हैं। इसके मद्देनज़र भाजपा ने हर बूथ पर मतदाता जोड़ने के लिए एक महीने का विशेष अभियान शुरू किया है। इसी तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने भी मतदाता सूची में संभावित गड़बड़ियों और नाम कटने के मुद्दों पर सवाल उठाए हैं और अपने कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची की निगरानी के लिए सक्रिय किया है। उधर मुस्लिम समाज भी न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जानबूझ कर पूर्व नियोजित तरीक़े से एक बड़ी साज़िश के तहत मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटे जाने की शिकायत कर रहा है।

उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में जहां भाजपा बनाम इण्डिया गठबंधन (कांग्रेस+समाजवादी पार्टी) चुनावी मुक़ाबला होने की संभावना थी वहीँ मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी शुरू से ही अपनी डफ़ली अलग ही बजा रही है। कुछ राजनैतिक विश्लेषक इसे मायावती द्वारा भाजपा को लाभ पहुँचाने की कोशिश की नज़र से भी देख रहे हैं। परन्तु पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी की ए आई एम आई एम ने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से लोकसभा सांसद और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रेशखर की आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) से चुनाव पूर्व समझौता कर उत्तर प्रदेश के राजनैतिक हल्क़ों में खलबली पैदा कर दी है। बसपा जैसे दलों की सक्रियता से मुस्लिम वोटों के बंटवारे की संभावना पर जहां पहले भी चर्चा होती रही है वहीँ चुनाव नज़दीक आने पर बने ओवैसी चंद्रशेखर के यह नये समीकरण व इसके द्वारा उठाये जाने वाले धर्मस्थल विध्वंस,लक्षित एस आई आर,अवैध घुसपैठ, धर्मांतरण, धार्मिक जुलूसों जैसे अनेक ऐतिहासिक विवादों पर तीखे बयान सामाजिक और साम्प्रदायिक संवेदनशीलता को और भी बढ़ा रहे हैं। गोया उत्तर प्रदेश के लगभग 19-20% मुस्लिम मतदाताओं के रुझान को लेकर एक ओर जहां सपा-कांग्रेस गठबंधन इस वोट बैंक को एकजुट रखने का प्रयास कर रहे थे वहीं असदुद्दीन ओवैसी के ए आई एम आई एम व चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) और बसपा जैसे दलों की सक्रियता से मुस्लिम वोटों के बंटवारे की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है। कुछ राजनैतिक विश्लेषक तो पहले ही असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा के हितसाधक नेता के रूप में देखते आ रहे थे परन्तु अब इस सूची में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भी शामिल हो गया है।

उधर भाजपा समर्थित बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री जोकि पहले भी अपने सम्प्रदायिकपूर्ण व विवादित बयानों के लिये चर्चा में बने रहते हैं उन्होंने पिछले दिनों हमारे राम तुम्हारे कृष्ण जैसी बातें कर और साथ ही भगवान कृष्ण को लेकर अशोभनीय बातें कर समाज में रोष भड़का दिया है। इसके बाद बेशक धीरेन्द्र शास्त्री ने मुआफ़ी मांग ली है परन्तु उनके समर्थन और विरोध को लेकर खिंची रेखायें साफ़ दिखाई दे रही हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की राजनीति में ब्राह्मण लॉबी और राजपूत/ठाकुर असंतोष जैसे मुद्दे भी चर्चा में हैं। जबकि बहुजन समाज पार्टी के कोर जाटव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए सपा, भाजपा और चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी के बीच होड़ देखी जा रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी द्वारा राम जन्म भूमि आंदोलन का पूरा लाभ उठा लेने के बाद और साथ ही मंदिर के दान व चंदा चोरी जैसे आरोपों में घिरने के बाद अब मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाये जाने के भी चर्चा सुनी जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि अधिकांश दलों द्वारा लगभग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उप-जातियों के आधार पर टिकट वितरण और प्रचार से स्थानीय स्तर पर जातीय वैमनस्य भी बढ़ सकता है। इसके अलावा चुनावों के बीच डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भ्रामक सूचनाओं और भड़काऊ कंटेंट के प्रसार से भी साम्प्रदायिक और जातीय तनाव भड़कने का जोखिम बना रहता है। इसीलिये 2027 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने के कारण इस चुनाव में आक्रामक बयानबाज़ी बढ़ने की पूरी आशंका है।



कहीं घूमने का है प्लान, पर करनी है घर की सफाई? जानें फास्ट होम क्लीनिंग आइडिया

संडे को सफाई और घूमने के बीच बैलेंस बनाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि गंदगी और अव्यवस्था से मन अशांत रहता है। ऐसे में कहीं घर को बुरी हालत में छोड़कर बाहर घूमने जाने का मन नहीं करता है। अगर आपके साथ भी हर वीकेंड पर कुछ ऐसी ही स्थिति बनी रहती है, तो यहां से फास्ट होम क्लीनिंग का आइडिया ले सकते हैं।

संडे को सफाई और घूमने के बीच बैलेंस बनाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन जल्दी-जल्दी क्लीनिंग करके आप समय से काम निपटा सकती हैं। साथ ही, अपने घूमने की प्लानिंग को भी सफल बना सकती हैं।, क्योंकि गंदगी और अव्यवस्था से मन अशांत रहता है। पूरे सप्ताह के बिजी शेड्युल में घर की साफ-सफाई कई दफा नजरंदाज हो जाती है और वीकेंड्स पर ही अच्छी तरह सफाई करने का मौका मिलता है। ऐसे में, घर को बिखरा हुआ छोड़कर कहीं बाहर घूमने जाने का मन नहीं करता है। अगर इस संडे आपका भी कहीं घूमने का प्लान है, लेकिन घर की सफाई बाकी है तो आप इन टिप्स को फॉलो करके आप घर की सफाई को जल्दी से निपटाकर अपने घूमने के प्लान को आराम से एंजॉय कर सकती हैं।

डेली डिक्लटरिंग से शुरुआत करें

सबसे पहले घर के उन हिस्सों को साफ करें, जो सबसे ज्यादा बिखरे हुए हैं।बेडरूम, लिविंग रूम और किचन से फालतू सामान हटाएं। डस्टबिन और वेस्ट बास्केट में गैरजरूरी चीजें डाल दें।

10 मिनट रूल अपनाएं

हर कमरे की सफाई के लिए सिर्फ 10 मिनट दें।वाइप करें, झाड़ू लगाएं और चीजों को सही जगह रखें। सफाई का सामान तैयार रखें। किचन क्लीनर, डस्टिंग क्लॉथ, वाइपर, ग्लास क्लीनर जैसी चीजें पहले ही निकालकर रखें। इससे बार-बार चीजें ढूंढने में समय नहीं लगेगा।

स्पॉट क्लीनिंग परदें ध्यान

पूरे घर की सफाई करने की बजाय, सिर्फ गंदे हिस्सों पर फोकस करें।फर्श, टेबल, डोर हैंडल और मिरर जैसी चीजें जल्दी साफ करें। सफाई करते समय वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दें और बर्तन धोने का काम भी साथ में करें। इससे समय की बचत होगी।

फर्श की सफाई स्मार्ट तरीके से करें

वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें या झाड़ू और पोछा एक साथ लगाएं।फर्श को एक बार वाइप कर दें ताकि धूल और गंदगी हट जाए।सफाई के बाद घर में फ्रेशनर का इस्तेमाल करें। इससे सफाई का असर और बेहतर लगेगा।

परिवार की मदद लें

सभी को एक-एक काम सौंपें, जैसे कोई झाड़ू लगाए, तो कोई धूल साफ करे।टीमवर्क से काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा।गहराई से सफाई करने के बजाय सिर्फ बेसिक क्लीनिंग पर फोकस करें। डीप क्लीनिंग के लिए किसी और दिन का चयन करें।



बच्चों के प्ले एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए अपनाएं ये तरीके

यह बात तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों को खेलना कितना पसंद आता है। अमूमन हम सभी बच्चों के खिलौनों और प्ले एरिया को क्लीन जरूर करते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ उसे डिसइंफेक्ट करना बेहद जरूरी है। दरअसल, इन सभी खिलौनों व प्ले एरिया पर बच्चे की चिपचिपी उंगलियों से लेकर फूड पार्टिकल्स तक रह जाते हैं, जिससे वहां पर बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं। ऐसे में बच्चे के प्ले एरिया को डिसइंफेक्ट करना आपको एक टफ टास्क लग सकता होगा। हालांकि, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो बेहद ही आसान तरीके से बच्चे के प्ले एरिया को डिसइंफेक्ट कर सकती हैं। फिर चाहे वह बच्चे के खिलौने हों या फिर उनकी खेलने की छोटी सी मेज, इन सबको डिसइंफेक्ट करने का बेहद ही आसान तरीका है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि बच्चे के प्ले एरिया को किस तरह डिसइंफेक्ट किया जाए-

पहले करें डिक्लटर

जब बात बच्चों के प्ले एरिया को डिइंफेक्ट करने की होती है तो इसकी शुरुआत हमेशा डिक्लटर करने से करें। आप बच्चे के सभी खिलौनों, किताबों और इधर-उधर पड़ी चीज़ों को हटाना शुरू करें। इससे प्ले एरिया को क्लीन करना अधिक आसान हो जाता है और यह सुनिश्चित होता है कि कोई छिपा हुआ कोना सफाई से छूट नहीं गया है।

बच्चों के लिए सुरक्षित डिसइंफेक्टेंट का करें इस्तेमाल

जब बात बच्चों के प्ले एरिया को डिसइंफेक्ट करने की हो तो आपको प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल थोड़ा समझदारी से करना चाहिए। ध्यान दें कि डिसइंफेक्टेंट किड्स सेफ हो। अगर आप चाहें तो एक भाग सफेद सिरका और 1 भाग पानी से घोल भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप डिसइंफेक्टेंट की मदद से बच्चे के खेलने की टेबल, कुर्सियां आदि को साफ करें। उन एरिया पर खासतौर से ध्यान दें जिन्हें अक्सर छुआ जाता है - जैसे कि खेलने की मेज या हैंडल के किनारे आदि।

खिलौनों को इस तरह करें साफ

बच्चे के खिलौनों को साफ करने के अलग-अलग तरीके अपनाएं। मसलन, प्लास्टिक और गैर-इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों को आप गर्म साबुन के पानी की बाल्टी में डालकर धोएं और हवा में सुखाएं। वहीं, सॉफ्ट टॉयज को ज्यादातर को वॉशिंग मशीन में डालकर क्लीन करें। अगर खिलौने इलेक्ट्रॉनिक हैं तो उसे नम कपड़े और डिसइंफेक्टेंट की मदद से पोंछें। ध्यान रहे कि आप उन्हें गीला न करें।

मैट और दीवारों की भी करें सफाई

यदि आपके बच्चे फोम या रबर प्ले मैट पर खेलते हैं, तो उन्हें भी डिसइंफेक्टेंट की मदद से क्लीन करें। खासतौर से, उन जगहों पर ज्यादा ध्यान दें, जहां पर गंदगी छिपी रहती है। इसी तरह, दीवारों, लाइट स्विच और आस-पास की खिड़कियों को डिसइंफेक्टेंट वाइप्स या माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछें।

वेंटिलेशन का भी रखें ध्यान

बच्चे के प्ले एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए उसे सिर्फ साफ करना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको वेंटिलेशन का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए। एक बार जब आप प्ले एरिया को क्लीन व डिसइंफेक्ट कर लेते हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए हवादार होने दें। इससे क्लीनिंग सॉल्यूशन जल्दी सूख जाते हैं और यह सुनिश्चित होता है कि कोई गंध नहीं रह जाती है।



बच्चों को बाहर घूमने या खेलने के लिए भेजने से पहले सिखाएं ये जरूरी सेफ्टी टिप्स

इस बात में कोई संदेह नहीं कि बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजना उनके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर आप भी अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेज रही हैं, तो कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन बातों की अनदेखी करना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अतिरिक्त भी सुरक्षा की दृष्टि से कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

बहुत दूर न हो खेलने की जगह

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों के खेलने की जगह घर से बहुत दूर नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि बच्चे ऐसी जगह खेलें, जहां से आप उन पर नजर रख सकें। बच्चे किन अन्य बच्चों के साथ खेलने जा रहे हैं, इसका भी पता रखें। बेहतर होगा कि बारी-बारी से किसी एक बच्चे के घर से कोई बड़ा भी उनके आसपास रहे।

मौसम का रखें ध्यान

सुरक्षा की बात करें, तो सबसे पहले आता है मौसम का ध्यान रखना। बच्चों को यह समझाकर रखें कि किस तरह के मौसम में बाहर नहीं जाना है और अगर पहले से बाहर खेलने के लिए निकले हैं, तो उन्हें तुरंत घर लौट आना है। जैसे, उन्हें बताकर रखें कि अगर घटाएं घिरने लगें और बारिश के आसार हों, तो तुरंत घर आ जाएं। बारिश में भीगना नुकसान कर सकता है। साथ ही बारिश में फिसलन के कारण खेलने पर चोट भी लग सकती है।

कीट-पतंगों का ध्यान रखें

बच्चे अगर पार्क में खेलते हैं तो वहां घास और पेड़-पौधों के कारण कीट-पतंगों का खतरा रहता है। इसलिए बच्चों को बग स्प्रे लगाकर भेजें। शाम के समय मच्छरों का प्रकोप बहुत होता है। इसलिए उनसे बचाव बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही बच्चों को समझा दें कि ऐसी जगह नहीं जाना है, जहां घास बड़ी हो। वहां खतरनाक कीटों का खतरा ज्यादा रहता है।

आसपास रखें नजर

बच्चों को समझाएं कि उन्हें अपने आसपास की गतिविधियों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। अगर कुछ अप्रत्याशित या अजीब लगे, तो तुरंत घर लौट आएं और बड़ों को बताएं। इसके अलावा उन्हें हमेशा ध्यान दिलाएं कि किसी भी अजनबी से बात नहीं करनी है। अजनबी के हाथ से कुछ खाना नहीं है। अजनबी से घुलना-मिलना घातक हो सकता है। अक्सर आपराधिक मानसिकता के लोग इसका लाभ उठाते हैं।

बाहर कुछ न खाएं

बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि उन्हें यह समझाकर भेजें कि बाहर की चीजें नहीं खानी हैं। और सबसे खास बात, किसी भी पार्क आदि जैसी जगहों पर पेड़ों पर लगे अनजान किस्म के फलों को कतई न खाएं। साथ ही उन्हें इस बात की सख्त हिदायत दें कि उन्हें अपने साथ के बच्चों के संग ही रहना है। अकेले इधर-उधर न जाएं।



इंस्टाग्राम पर कहीं आपका बच्चा भी तो नहीं देख रहा उल्टे-सीधे कंटेंट? ऐसे छुड़ाएं आदत

सोशल मीडिया वैसे तो दुनिया में चल रही चीजों से अप टू डेटेड रहने के लिए बड़ा काम का प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पर घंटों रील्स देख कर अपना समय बर्बाद करें। अक्सर ऐसा बच्चे और टीनएजर्स कर रहे हैं, जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।

कई बार ऐसा होता है कि रील्स स्क्रॉल करते हुए सामने कोई ऐसा कंटेंट आ जाते हैं, जो कि उन्हें नहीं देखना चाहिए। आज के समय में, टीनेज बच्चों को हैंडल करना माता-पिता के लिए काफी चैलेंजिंग हो गया है। खास कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मामले में बच्चे को बच्चे को समझाना और उन्हें इससे दूर रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। क्योंकि इस उम्र में उनकी फीडम और प्राइवेसी दोनों ही अहम हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में उनकी आदतों में सुधार कैसे लाया जाए, आइए इस बारे में हम आपको बताते हैं।

बच्चों को ब्रेक लेने के लिए समझाएं

इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते समय, बच्चे अक्सर अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। इससे उन्हें दूर रखने के लिए आप बच्चे को ब्रेक लेने के लिए कह सकते हैं। समय के महत्व को बताएं और उन्हें मोबाइल से ब्रेक लेकर खेल-कूद पर थोड़ा ध्यान देने पर फोकस करवाएं। अगर आपका टीनएजर इंस्टाग्राम पर घंटों समय बर्बाद कर रहा है, तो यह फीचर उन्हें एक टाइम बाद ब्रेक लेने की याद दिलाएगा। अक्सर बच्चे पढ़ते-पढ़ते भी बीच में मोबाइल उठा लेते हैं, तो यह फीचर बच्चों को रीसेट और रीफोकस करने में मदद कर सकता है। इसमें यूजर को यह मैसेज मिलता है कि उन्होंने अपनी डेली लिमिट का स्क्रीन टाइम इस्तेमाल कर लिया है।

क्वाइट मोड

इंस्टाग्राम का क्वाइट मोड सीमाएं तय करने के मामले में एक बेहतरीन फीचर है। इससे आपके बच्चे की लगातार स्क्रीन देखने की आदत में सुधार आ सकती है। यह फीचर 12 घंटे तक के लिए नोटिफिकेशन म्यूट करने में मदद करता है, जिससे बच्चे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की जगह पढ़ाई में अपना समय बिता सकते हैं। इसका ऑटो-रिप्लाई फीचर डीएम करने की कोशिश कर रहे लोगों को संदेश भेजता है कि पर्सन अभी क्वाइट मोड में है और उपलब्ध नहीं है।

नाइट नज

मोबाइल देखने की लत से रात की नींद की क्वालिटी को बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। ऐसे में बच्चों को इंस्टाग्राम से दूर रखने के लिए इसका नाइट नज टूल भी है, जो आपकी इस परेशानी का हल आसानी से कर सकता है। इस फीचर के तहत यूजर को याद दिलाते हुए एक रिमाइंडर मैसेज भेजा जाता है कि रात हो रही है और सोने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर आपका बच्चा रात 10.00 बजे से सुबह 7.00 बजे के बीच 10 मिनट से अधिक समय तक इंस्टाग्राम का उपयोग करता है, तो यह फीचर हर 10 मिनट में एक फ्रेंडली रिमाइंडर भेजता है।

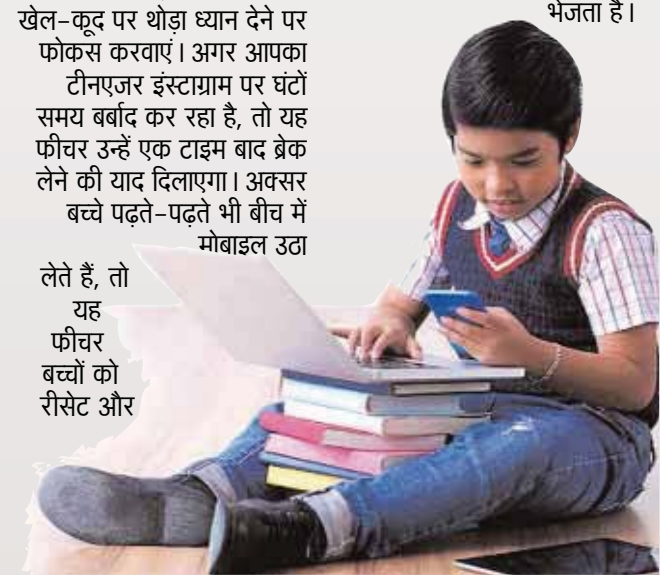



होम गार्डनिंग शुरू करने के 5 आसान टिप्स

अपने घर के अगल बगल हरियाली किसको पसंद नहीं होती है। हालांकि शहरों में हरियाली न होने के कारण ज्यादातर लोग खुद का गार्डन बनाना पसंद करते हैं। कई लोग अपने गार्डन में केवल फूल रखते हैं तो कई लोग अपने गार्डन में सब्जियों की खेती भी करते हैं। गार्डन छोटा हो या बड़ा आप चाहें तो आसानी से उसमें अपनी पसंदीदा चीज़ों को उगा सकती हैं।

उचित स्थान चुने

गार्डनिंग करने के लिए जरूरी है आपको सही जगह का चयन करना। अगर आपके पास गार्डन नहीं है तो आप अपनी बालकनी में भी गार्डनिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिट्टी के गमले ख़रीदने होंगे।

अच्छे बीज चुनें

गार्डनिंग आप कहीं भी क्यों न कर रहे हो आप को सही तरीके का बीज चाहिए होगा। बीज जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी आपके पौधे में सब्जी और फूल प्राप्त होंगे। बीज खरीदते समय आपको खास ध्यान देना होगा।

कौन सा गमला होगा बेस्ट

अगर आप पौधों में सब्जियां फल उगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको मिट्टी का गमला ही खरीदना चाहिए। मिट्टी के गमले में पौधे की ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी होती है। नहीं ऐसे में इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान होता है।

सही मिट्टी का चयन करें

पौधों की ग्रोथ के लिए मिट्टी का चयन करना काफी ज्यादा ज़रूरी है। मिट्टी लेते समय ध्यान रखें कि मिट्टी ना तो ज्यादा हार्ड हो और ना ही ज्यादा चिपचिपा। पौधे लगाने के लिए मिट्टी निम्न प्रकार की होनी चाहिए। इससे पौधे अच्छे उठते हैं।

पौधे को समय पर पानी दें

पौधों की सही तरीके से ग्रोथ चाहते हैं तो आपको होम गार्डनिंग के दौरान भी पौधों को समय समय पर पानी देते रहना चाहिए। इससे आपके पौधे की ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी होती है। अगर आप इन बातों को फ़ॉलो करते हैं तो आपका हूँ गार्डनिंग करने का सपना पूरा हो सकता है।

दिसंबर के पहले सप्ताह में बाजार में दस्तक देंगे दो आईपीओ

नई दिल्ली ।

भारतीय पूंजी बाजार में आगामी सप्ताह निवेशकों के लिए कई नए अवसर लेकर आ रहा है। दिसंबर के पहले सप्ताह में मोनोमार्क इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड और मातंगी रबर लिमिटेड समेत चार कंपनियां अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लेकर आ रही हैं। इन कंपनियों का मकसद कारोबार विस्तार और कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करना है। दिसंबर के पहले सप्ताह में मोनोमार्क इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड और मातंगी रबर लिमिटेड पूंजी जुटाने के लिए अपना आईपीओ ला रही हैं। मोनोमार्क इंजीनियरिंग का आईपीओ 2 से 4 दिसंबर तक खुला रहेगा, जबकि मातंगी रबर का सार्वजनिक निर्गम 1 से 3 दिसंबर तक अभिदान के लिए उपलब्ध होगा। दोनों कंपनियां अपने आईपीओ खुलने से ठीक पहले एंकर निवेशकों के लिए बोली आयोजित करेंगी, मातंगी रबर के लिए 30 नवंबर को और मोनोमार्क इंजीनियरिंग के लिए 1 दिसंबर को। इसके अतिरिक्त नवंबर के अंतिम सप्ताह में भी दो अन्य आईपीओ बाजार में आएंगे। खाद्य सेवा क्षेत्र में कार्यरत फूडलिंक एफएंडबी होल्डिंग्स (इंडिया) लिमिटेड का आईपीओ 26 नवंबर को लॉन्च होगा। वहीं, निजी इक्विटी फर्म एवरस्टोन कैपिटल समर्थित चिकित्सा प्रौद्योगिकी मंच इंटेग्रिस मेडटेक अपना सार्वजनिक निर्गम 27 नवंबर को पेश करेगा, जिससे निवेशकों के पास विविध क्षेत्रों में निवेश के कई विकल्प उपलब्ध होंगे।

भारत-यूरोपीय संघ एफटीए से व्यापार, निवेश के नए अवसर खुलेंगे- जर्मन राज्य प्रमुख

प्रस्तावित समझौता दोनों पक्षों के लिए रोजगार, निवेश और व्यापार के नए द्वार खोलेगा

नई दिल्ली ।

जर्मनी के लोअर सैक्सोनी राज्य के प्रमुख ओलाफ लीस ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) दोनों पक्षों के बीच निवेश, व्यापार और रोजगार के नए अवसर खोलेगा। इस समझौते पर दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जबकि इसकी बातचीत जनवरी में पूरी हो चुकी है। भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा पर आए लीस ने नई दिल्ली स्थित जर्मनी दूतावास में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एफटीए हमारे देशों के बीच अधिक निवेश, अधिक व्यापार और अधिक कारोबार के लिए एक बड़ा अवसर है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस साल के अंत तक एफटीए को लेकर कोई समाधान निकल आएगा। करीब 60 राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे लीस ने बताया कि यह समझौता भारत में निवेश करने की इच्छुक उनकी राज्य की कंपनियों के साथ ही जर्मनी में अवसर तलाश रहे भारतीय व्यवसायों को भी लाभ पहुंचाएगा। लीस अपनी यात्रा के दौरान दिल्ली, पुणे और मुंबई में बैठकें करेंगे। लोअर सैक्सोनी जर्मनी के प्रमुख राज्यों में से एक है।

बाजार की चाल से न बिगड़े निवेश का संतुलन, रीबैलेंसिंग से रखें जोखिम काबू में

एसेट एलोकेशन ड्रिफ्ट से बचें, जानें कब और कैसे करें निवेश पोर्टफोलियो को रीबैलेंस

नई दिल्ली ।

शेयर बाजार में लगातार तेजी निवेशकों के लिए खुशी लाती है, लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण चुनौती भी पैदा होती है। यह तेजी आपके इक्विटी निवेश की वैल्यू को इतना बढ़ा सकती है कि आपके पूरे पोर्टफोलियो का जोखिम स्तर अनजाने में ही बढ़ जाए। इस स्थिति से बचने और अपने निवेश को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप रखने के लिए पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है। निवेशक आमतौर पर अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम क्षमता के आधार पर इक्विटी और डेट जैसे एसेट क्लास में एक निश्चित अनुपात तय करते हैं। हालांकि, बाजार में तेजी आने पर इक्विटी की वैल्यू तेजी से बढ़ती है, जिससे यह अनुपात बिगड़ जाता है। मान लीजिए, 60 फीसदी वाला पोर्टफोलियो बढ़कर 68 फीसदी इक्विटी का हो जाए, तो इसे एसेट एलोकेशन ड्रिफ्ट कहते हैं। यह ड्रिफ्ट आपके पोर्टफोलियो का जोखिम बढ़ा देता है, भले ही आपने कोई नया निवेश न किया हो। इस ड्रिफ्ट को ठीक करने और मूल एसेट एलोकेशन पर लौटने की प्रक्रिया को पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य निवेश के जोखिम को आपकी क्षमता के अनुसार नियंत्रित रखना और यह सुनिश्चित करना है कि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में सही ट्रैक पर रहें। यह प्रक्रिया रोज या हर महीने करने की बजाय, साल में एक बार किसी तय तारीख पर करनी चाहिए।

निजी निवेश में ज़बरदस्त उछाल- सीआईआई रिपोर्ट

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में परियोजना घोषणाएं 26.6 लाख करोड़ पहुंचीं

नई दिल्ली ।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में निजी क्षेत्र के निवेश में उल्लेखनीय तेजी आई है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में निजी क्षेत्र की नई परियोजना घोषणाएं सालाना आधार पर 58.5 प्रतिशत बढ़कर 26.6 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गईं। यह वृद्धि सरकारी नीतिगत सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और बढ़ते निवेशक भरोसे का प्रमाण है। सीआईआई के निजी निवेश सूचक के दूसरे संस्करण में बताया गया कि इस अवधि में कुल परियोजना घोषणाओं में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 86.2 प्रतिशत रही, जो पिछले साल 74.2 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा पिछले दशक की समान अवधियों के औसत का 4.4 गुना है। सीआईआई के एक अभिधकारी ने इस सफलता का श्रेय सरकार के सतत नीतिगत सुधारों और नियामकीय ढांचे में सुधार को दिया, जिससे निजी निवेश के लिए एक मजबूत अनुकूल माहौल बना है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग इन अवसरों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है। रिपोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि यह सुधार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक पूंजी निर्माण में भी परिलक्षित हो रहा है। लगभग 1,800 सूचीबद्ध निजी कंपनियों का सकल पूंजी निर्माण वित्त वर्ष 2025-26 में 12.4 लाख करोड़ रुपये रहा, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.6 प्रतिशत है।

सोने और चांदी की कीमतों में फिर से उछाल

सोना 1,26,021 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 1,54,205 रुपए प्रति किलो

नई दिल्ली ।

सोने और चांदी की कीमतों में फिर से उछाल देखने को मिला है। गुरु नानक जयंती के अवसर पर शेयर बाजार पूरे दिन बंद हैं, हालांकि वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर शाम के सत्र में कारोबार जारी रहेगा।

ऐसे में पिछले कारोबारी दिन के बंद भाव और सुबह के सांकेतिक खुदरा दरों के आधार पर मंगलवार को सोने और चांदी दोनों में तेजी दर्ज की गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर 24 कैरेट सोना 4,243 रुपये की तेजी के साथ 1,26,021 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।

पिछले कारोबारी दिन यह 1,21,778 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियंस डॉट को डॉट इन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का दाम 1,27,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट का सोना 1,24,945 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,14,450 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। चांदी के दामों में भी बड़ा उछाल आया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर चांदी का भाव 6,392 रुपये की तेजी के साथ 1,54,205 रुपये प्रति किलो हो गया है। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,47,813 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

टाटा स्टील-एपीएल अपोलो मेगा डील-शेयर लुढ़के,कर्ज बढ़ा,भविष्य की संभावनाएं

28,000 करोड़ के सौदे में टाटा स्टील चुकाएगी ऊंची कीमत

नई दिल्ली ।

देश के स्टील सेक्टर में एक बड़ी हलचल के तहत टाटा स्टील और एपीएल अपोलो ट्यूब्स के बीच लगभग 28,000 करोड़ रुपये की एक मेगा डील चर्चा में है। इस सौदे के तहत टाटा स्टील, एपीएल अपोलो में 52.6 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है, साथ ही अपना ट्यूब और कलर कोटेड कारोबार एपीएल अपोलो को बेचेगी। इस खबर से निवेशकों में चिंता बढ़ गई, जिसके चलते 23 नवंबर, को टाटा स्टील के शेयर 8 फीसदी और एपीएल अपोलो के शेयर 21 फीसदी से अधिक गिर गए। यह मेगा डील दोनों कंपनियों के कारोबार में बड़ा बदलाव लाने वाली है। टाटा स्टील एपीएल अपोलो में 52.6 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए अधिकतम 32,266 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है। इसके समानांतर, वह अपना ट्यूब कारोबार और टाटा स्टील कलर्स का पूरा कारोबार 28,000 करोड़ रुपये में एपीएल अपोलो को बेचेगी। हालांकि, इस सौदे की खबर के साथ ही शुरुआती खर्च, बढ़ते कर्ज और कमाई पर दबाव की आशंका ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी।

जानकारों का मानना है कि टाटा स्टील एपीएल अपोलो की हिस्सेदारी के लिए काफी ऊंची कीमत चुका रही है, जिसकी एंटरप्राइज वैल्यू करीब 60,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। डील के बाद टाटा स्टील के कर्ज का बोझ बढ़ने का अनुमान है। सितंबर 2026 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट डेट 91,400 करोड़ रुपये था, जो सौदा पूरा होने के बाद लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

यानी, कंपनी पर करीब 28,600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज चढ़ेगा, जिससे कर्ज घटाने की रफ्तार धीमी हो सकती है। शुरुआती दो-तीन साल तक इस डील का टाटा स्टील की प्रति शेयर कमाई पर नकारात्मक असर दिखने की आशंका है। इसके बावजूद, इस सौदे से टाटा स्टील को एपीएल अपोलो का मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ब्रांड और देशव्यापी कारोबार मिलेगा, जिससे भविष्य में स्टील पाइप और कलर कोटेड प्रोडक्ट के बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी बढ़ेगी। दोनों कंपनियों की संयुक्त उत्पादन क्षमता वर्तमान में 75 लाख टन सालाना है, जिसे अगले 5-6 सालों में बढ़ाकर 1.55 करोड़ टन सालाना करने की योजना है। प्रबंधन को उम्मीद है कि नए कारोबार से 4-5 साल में करीब 10,000 करोड़ रुपये के एबिटा की क्षमता बन सकती है और साढ़े तीन साल में ईपीएस पर सकारात्मक असर दिखेगा।

विशेषज्ञों ने टाटा स्टील के शेयर पर खरीदारी की रेटिंग बरकरार रखते हुए 219 रुपये का अपसाइड टारगेट दिया है, यह मानते हुए कि डील महंगी जरूर है, पर जुड़े जोखिमों का काफी असर शेयर के भाव में पहले ही दिख चुका है।

आरबीआई बैठक से पहले कंपनियों की फंड रेसिंग, 25,000 करोड़ जुटाने की तैयारी

0.25 फीसदी से 0.50 फीसदी तक रेपो रेट में बढ़ोतरी का अनुमान

नई दिल्ली ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अगली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक से पहले देश की कंपनियां सक्रिय हो गई हैं। करीब 25,000 करोड़ रुपए बॉन्ड जारी कर जुटाने की तैयारी की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी से पहले मौजूदा कम लागत पर लंबी अवधि का कर्ज सुरक्षित करना है। एमपीसी की बैठक 2 से 4 दिसंबर तक होनी है। रॉयटर्स के सर्वे और बाजार विश्लेषकों के अनुसार आरबीआई रेपो रेट में 0.25 फीसदी से 0.50 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकता है। इससे पहले आरबीआई ने 7 अक्टूबर को रेपो रेट को 0.25 फीसदी बढ़ाकर 5.50 फीसदी कर दिया था और अपनी नीति का रुख कैलिब्रेटेड टाइटनिंग कर दिया था, जिसका अर्थ है महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर आगे भी दरें बढ़ाने की संभावना। इस संभावित बढ़ोतरी से बचने के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी), स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (एसआईडीबीआई), जियो क्रेडिट, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और टोरेंट पावर जैसी सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियां बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाने में लगी हैं। नवंबर में-एएए रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड की यील्ड में 0.20 फीसदी से 0.30 फीसदी तक की गिरावट आई है, जिसे कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, विदेशी निवेशकों की वापसी और रुपए की स्थिरता जैसे कारकों का समर्थन मिला है। इसी मौके का लाभ उठाकर कंपनियां अपनी उधारी लागत को नियंत्रित रखना चाहती हैं। नवंबर में अब तक 90,000 करोड़ रुपए निजी बॉन्ड प्लेसमेंट के जरिए जुटाए जा चुके हैं, और इस साल कुल फंड जुटाने का आंकड़ा लगातार दूसरे साल 10 लाख करोड़ रुपए पार कर सकता है। रेपो रेट में वृद्धि से बैंकों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है, जिसका सीधा असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई पर पड़ सकता है।

ट्रंप के दबाव में एनवीडिया ने जेनसेन हुआंग को सीईओ पद पर किया बहाल

अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से हुई कृत्रिम मेधा कंपनी के शीर्ष पद पर बहाली

न्यूयॉर्क ।

कृत्रिम मेधा (एआई) क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एनवीडिया ने अपने सह-संस्थापक जेनसेन हुआंग को सीईओ के पद पर बहाल कर दिया है। विवाहेतर संबंधों के आरोपों के चलते हुए उनके इस्तीफे के बाद यह एक चौंकाने वाला घटनाक्रम है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सक्रिय हस्तक्षेप ने उनकी पद पर वापसी का मार्ग प्रशस्त किया, जबकि पहले निदेशक मंडल ने उनकी पेशकश को ठुकरा दिया था। हुआंग ने 12 नवंबर को इस्तीफा दिया था, जिसके बाद कोलेट क्रेस अंतरिम सीईओ बनीं। उनके इस्तीफे की वजह एक चीनी कारोबारी महिला और कंपनी की ही कर्मचारी से कथित संबंध थे। निदेशक मंडल ने वापसी की उनकी पेशकश को पहले ठुकरा दिया था, भले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एफबीआई जांच की बात करते हुए भी उनकी प्रशंसा की थी। उनके समर्थन में स्टैंड विद जेनसेन अभियान चला, जिसे एलन मस्क सहित कई हस्तियों का साथ मिला। राष्ट्रपति ट्रंप ने 16 नवंबर को सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें हुआंग की वापसी पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

सेबी ने आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम पर लगाई रोक,निवेशकों को आगाह किया

बाजार मध्यस्थों को प्रचार-प्रसार से रोका, निवेशकों को अनौपचारिक सौदों से बचने की सलाह

नई दिल्ली । बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आगामी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) के आंकड़ों के प्रकाशन और प्रचार-प्रसार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। नियामक ने बाजार मध्यस्थों और अन्य प्रतिभागियों को इस तरह की गतिविधियों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सेबी ने निवेशकों को जीएमपी को संभावित लिस्टिंग मूल्य या अपेक्षित रिटर्न का संकेतक न मानने की सख्त चेतावनी दी है। सेबी ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि जीएमपी उन अनौपचारिक और अपुष्ट कीमतों को दर्शाता है जिन पर किसी कंपनी के शेयर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से पहले कारोबार किए जाने का दावा किया जाता है। ये सौदे मान्यता-प्राप्त शेयर बाजारों के दायरे से बाहर होते हैं, जिस पर कोई नियामकीय निगरानी नहीं होती और न ही इनमें निवेशकों को कोई सुरक्षा या सौदे के निपटान की गारंटी मिलती है। नियामक ने पाया कि जीएमपी के आंकड़े वेबसाइटों, डिजिटल मंचों, समाचार पत्रों और यहां तक कि सेबी में पंजीकृत कुछ मध्यस्थों द्वारा भी व्यापक रूप से प्रकाशित किए जा रहे थे। नियामक ने स्पष्ट किया कि ऐसे प्रीमियम के आंकड़ों का प्रकाशन निवेशकों के हितों के लिए नुकसानदेह है और प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता व जवाबदेही के सिद्धांतों के विपरीत है। सेबी ने अपने सभी पंजीकृत मध्यस्थों और बाजार प्रतिभागियों को अपनी वेबसाइट, डिजिटल मंचों, ईमेल, एसएमएस और सोशल मीडिया सहित किसी भी संचार माध्यम पर आईपीओ के जीएमपी के आंकड़े प्रकाशित, प्रदर्शित या प्रसारित नहीं करने का निर्देश दिया है।

धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज

जबलपुर ।

लार्डगंज और गोरखपुर थाना क्षेत्र में तीन सायबर ठगी के मामले सामने आए हैं7 लार्डगंज थाना क्षेत्र में ट्योरिन सोलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 3 कर्मचारियों पर धोखाधड़ी कर दूसरी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। वहीं लार्डगंज में आईफोन दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 62 हजार 940 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसी प्रकार गोरखपुर थाना क्षेत्र में झाड़-फूंक के जरिए बीमारी और घरेलू परेशानियां दूर करने तथा धन दोगुना करने का झांसा देकर एक महिला से करीब 5 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है।

लार्डगंज पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार राइट टाउन निवासी 36 वर्षीय कंपनी संचालक अभिषेक बाधवा कंपनी के कर्मचारी सुमित सेन, सुभाष विश्वकर्मा और मोहम्मद फजल तबिश दूसरी कंपनियों के लिए भी काम कर रहे थे। कर्मचारियों ने कंपनी के नाम से फर्जी एनओसी तैयार कर दूसरी कंपनियों को सोलर प्लांट लगवाने का काम दिलाया। कंपनी के कंप्यूटर की जांच में 14-15 अन्य कंपनियों का डेटा और करीब 70-75 ऑर्डर से जुड़े काम के प्रमाण मिले। साथ ही कंपनी के डायरेक्टर के फोटो, फोटोशॉप से तैयार हस्ताक्षर, कंपनी की सील, ऑडिट रिपोर्ट और व्हाट्सएप चैट में पैसों के लेन-देन से जुड़े साक्ष्य मिलने की बात सामने आई।

इसी प्रकार राइट टाउन स्थित अतुल बिहार अपार्टमेंट निवासी 51 वर्षीय अरुण अग्रवाल गत 27 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 2 बजे एक मोबाइल नंबर से उन्हें आईफोन दिलाने का ऑफर दिया गया था। इसके झांसे में आकर उन्होंने यूपीआई के माध्यम से 499 रुपए से शुरुआत करते हुए कुल 62 हजार 940 रुपए अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए। रकम जमा कराने के बाद भी उन्हें आईफोन नहीं दिया गया। पीड़ित ने कई बार संबंधित व्यक्ति से अपने रुपए वापस मांगे, लेकिन वह गाली-गलौज करने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोपी ने अपना नाम मनीष जैन बताया था। शिकायत के मुताबिक, रकम बाके बिहारी सर्विस सेंटर, राहुल खान, यकीन खान और वारिस हरसोनिया के खातों में जमा कराई गई थी।

इसी तरह गोरखपुर में ककरैया तलैया गोरखपुर निवासी 48 वर्षीय आरती मेहरा कुछ समय से बीमार थी और घर में भी कई तरह की परेशानियां चल रही थीं।

दस्तावेज गुम करने पर एसबीआई को 60 लाख का चूना, बुजुर्ग की जीत

2019 में चुकाया था होम लोन, बैंक ने नहीं लौटाए थे संपत्ति के असली कागजात

नई दिल्ली ।

उपभोक्ता अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को एक 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को लगभग 60 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला बैंक द्वारा होम लोन का पूरा भुगतान करने के बावजूद संपत्ति के असली कागजात न लौटाने के एक लंबे समय से चले आ रहे मामले में आया है। कोर्ट ने बैंक को न सिर्फ मुआवजा देने, बल्कि जल्द से जल्द संपत्ति के पूरे दस्तावेज वापस करने का भी निर्देश दिया है। यह मामला अलीगढ़ के गुलवीर सिंह चौहान से जुड़ा है, जिन्होंने 1997 में एसबीआई की सिटी ब्रांच से होम लोन लिया था और अपनी संपत्ति का असली सेल डीड बैंक के पास गिरवी रखा था। चौहान ने 13 मई 2019 को अपना पूरा बकाया लोन चुका दिया और बैंक से नो-ड्यूज सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया। हालांकि, इसके बावजूद बैंक बार-बार अनुरोध करने पर भी उनके असली दस्तावेज वापस नहीं कर पाया और अंततः स्वीकार किया कि दस्तावेज गुम हो गए हैं। दस्तावेजों के अभाव में चौहान को मालिकाना हक की पुष्टि करने, नया लोन लेने या संपत्ति हस्तांतरित करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिरकार, 13 जून 2023 को गुलवीर सिंह चौहान ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। कार्यवाही के दौरान एसबीआई ने दस्तावेज मिलने की बात तो स्वीकार की, लेकिन चौहान के आरोपों का खंडन किया। आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत ने बैंक के 13 फरवरी 2020 के पत्र की जांच की, जिससे पुष्टि हुई कि चौहान ने मई 2019 में ही सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया था। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि ऋण चुकाने के बाद भी दस्तावेज न लौटाना सेवा में कमी है।

जेएसडब्ल्यू मोटर्स और एआरएआई में नए ऊर्जा वाहन विकास हेतु समझौता

नई दिल्ली ।

जेएसडब्ल्यू समूह की यात्री वाहन इकाई, जेएसडब्ल्यू मोटर्स ने नए ऊर्जा वाहनों (एनईवी) के संयुक्त विकास, परीक्षण और स्थानीयकरण के लिए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य वाहनों और उनकी प्रणालियों के विकास के लिए मजबूत तकनीकी आधार तैयार करना, परीक्षण एवं नियामकीय तैयारियों को बेहतर बनाना है। कंपनी विशेष रूप से भारतीय परिचालन स्थितियों के अनुकूल प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं का विकास करना चाहती है। जेएसडब्ल्यू मोटर्स के एक वरिष्ठ अभिधकारी ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल वाहन बनाना नहीं, बल्कि मजबूत स्वदेशी इंजीनियरिंग क्षमताओं वाली विश्वस्तरीय भारतीय वाहन कंपनी बनाना है।

उन्होंने जोर दिया कि यह साझेदारी भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अगली पीढ़ी के परिवहन समाधान विकसित करने में तेजी लाएगी।

अमेरिका में दोहरे तूफानों का कहर, उड़ाने और छुट्टियों पर होगा असर



वॉशिंगटन। अमेरिका में थैंक्सगिविंग की छुट्टियों से ठीक पहले मौसम ने गंभीर रूप ले लिया है। देश के पूर्वी और पश्चिमी तट पर दो शक्तिशाली तूफानों के एक साथ सक्रिय होने से कई राज्यों में भारी बारिश, बर्फबारी, तेज हवाओं और बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। समुद्र में उठने वाली असामान्य ऊंची लहरें, जिन्हें किंग टाइड कहा जाता है, स्थिति को और गंभीर बना सकती हैं। मौसम विभाग ने 10 से अधिक राज्यों में खराब मौसम की चेतावनी जारी की है, जिसका असर छुट्टियों के दौरान यात्रा करने वाले लाखों लोगों पर पड़ सकता है। अमेरिका के पश्चिमी तट पर तूफान का असर सोमवार से दिखाई देने लगा। प्रशांत महासागर के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में सक्रिय मौसमी प्रणाली समुद्र में ऊंची लहरें पैदा कर रही है। मंगलवार से थैंक्सगिविंग डे तक समुद्र का जलस्तर काफी ऊंचा रहने का अनुमान है। सैन फ्रांसिस्को में बुधवार सुबह करीब 11 बजे हाई टाइड के दौरान समुद्र का स्तर 1983 में बने रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच सकता है। इससे तटीय इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ गया है। कैलिफोर्निया के बे एरिया में मंगलवार और बुधवार के बीच करीब एक इंच बारिश होने का अनुमान है, जबकि तटीय क्षेत्रों में 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। समुद्र के नजदीक स्थित सैन फ्रांसिस्को और ओकलैंड के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जलभराव का खतरा जताया गया है, हालांकि हवाई अड्डा प्रशासन ने ऊंचे जलस्तर से निपटने के लिए तैयारियों का दावा किया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से बुधवार दोपहर तक गैर-जरूरी यात्रा टालने की अपील की है। बे एरिया के तटीय इलाकों में समुद्र की ऊंची लहरें चट्टानों से टकरा रही हैं, जिससे स्थानीय निवासियों ने घर में झटके महसूस करने की बात कही है। गुरुवार को एक दूसरा तूफान वॉशिंगटन और पश्चिमी ओरेगन की ओर बढ़ सकता है, जिससे भारी बारिश और कैस्केड पहाड़ियों में बर्फबारी की आशंका है। दूसरी ओर, पूर्वी तट पर बुधवार को नया तूफान सक्रिय होने का अनुमान है। फ्लोरिडा के ब्रेवार्ड काउंटी, ट्रेजर कोस्ट और ओकीचोबी काउंटी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है।

कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास का पासपोर्ट जब्त भी हो सकता है! सबूत मांगे गए

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरभ दास की 'उड़ान' पर लगी रोक की वजह से नया विवाद खड़ा हो गया है। सीजेपी के नेता जहां सरकार पर परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं तो वहीं इसके पीछे सौरभ दास के दस्तावेजों में कुछ खामियों की बात सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक, सौरभ दास के आधार, पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों में कुछ जानकारियों में अंतर बताते हुए कुछ शिकायतें की गई हैं, जिसकी वजह से चेन्नई रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (आरपीओ) ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू किया है। जब तक



इस मामले का निपटारा नहीं कर दिया जाता है तब तक वह विदेश की यात्रा नहीं कर पाएंगे।

गौरतलब है कि पासपोर्ट जारी करने से पहले या बाद में (तत्काल पासपोर्ट के मामले में) पुलिस वेरिफिकेशन की जाती है। लेकिन यदि बाद में भी यदि कोई गलत जानकारी या विसंगति की बात सामने आती है तो आरपीओ से कारण बताओ नोटिस जारी करके दोबारा वेरिफिकेशन कराया जा सकता है। पासपोर्टधारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा जाता है कि क्यों ना आपके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाए। उन्हें दोबारा दस्तावेजों के साथ अपनी बात रखनी होती है और यदि इससे सबकुछ सही होने की पुष्टि नहीं होती है तो पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है।

इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। सौरभ दास को लेकर कुछ शिकायतें मिलने के बाद एक नोटिस सीजेपी नेता को सोमवार शाम को भेजा गया था। इसमें उन्हें सात दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ यह साबित करने को कहा गया है कि जो 'जन्मस्थान' उन्होंने पहले बताया था वह वास्तविक है। उन्हें दस्तावेजों के साथ अपने ब्यौरों को सही साबित करने को कहा गया है यदि दास ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पासपोर्ट ऐक्ट 1967 की धारा 10 (b) के तहत इसे जब्त किया जा सकता है। नोटिस में उन्हें कहा गया है कि जब तक जवाब नहीं दाखिल कर देते पासपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि यदि शाम को ही सौरभ दास को नोटिस ईमेल पर मिल गया था तो वह देर रात एयरपोर्ट पर क्यों पहुंचे? जहां कुछ आलोचकों का कहना है कि विक्टिम कार्ड खेलने के लिए सौरभ दास एयरपोर्ट गए और वहां जाकर वीडियो बनाया। वहीं, सीजेपी नेता ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे और इसलिए ईमेल नहीं देख पाए थे। उन्हें एयरपोर्ट पर ही पोसपोर्ट फ्लैग किए जाने की जानकारी दी गई और ईमेल चेक करने को कहा गया।

सौरभ दास के पास जवाब देने के लिए 30 नंवबर तक का समय है। उन्हें दस्तावेजों के साथ आरपीओ में अपना जवाब दाखिल करना होगा और यह साबित करना होगा कि उनकी ओर से 2019 में दी गई सभी जानकारियां सही थीं। यदि वह ऐसा कर पाते हैं तो दोबारा अपने पासपोर्ट के जरिए उड़ान भर पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक हाल के समय में दास की जन्मतिथि, जन्म स्थान, पता, पिता के नाम आदि को लेकर कई शिकायतें की गई हैं। दावा किया गया है कि आधार, पासपोर्ट और स्कूल सर्टिफिकेट में उनके ब्योरों में अंतर है। हाल ही में एक पीआईएल भी मद्रास हाई कोर्ट में दायर की गई है और सौरभ दास की नागरिकता की जांच की मांग उठाई गई है।

सपा की पहली लिस्ट से सुलगी 'सीट शेयरिंग' की रार, इमरान मसूद की तल्खी के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटे दोनों दल

नई दिल्लीः 'उनको अच्छी नहीं लगती बुलंदी मेरी, उनको शायद मेरी परवाज बहुत खलती है...', समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से सीट शेयरिंग की बातचीत के बीच अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की तो नाराज कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का अंदाज-ए-बयां कुछ ऐसा था. इमरान मसूद ने यहां तक कह दिया कि हम कोई भिखारी नहीं हैं. कांग्रेस जब चाहेगी, अपने उम्मीदवार उतारेगी. इसमें बड़ी बात क्या है? अगर आप गठबंधन के बीच ऐसा बर्ताव करते हैं, तो यह गठबंधन नहीं है. इसका मतलब है कि आपकी तरफ से कोई गंभीरता नहीं है. इमरान मसूद के इस तल्ख बयान के बाद लगा कि गठबंधन अब संभव नहीं, लेकिन अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की ओर से डैमेज कंट्रोल शुरू हो



गया है. दोनों पार्टियों के नेता गठबंधन में किसी भी तरह के विवाद से इनकार कर रहे हैं, लेकिन बयानों से साफ है कि सीटों को लेकर अंदरखाने सहमति बनना आसान नहीं है. इमरान मसूद की नाराजगी पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह ने कहा कि पार्टी वही रणनीति अपना रही है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपनाई गई थी. उस समय भी सीटों को लेकर बातचीत जारी थी और सपा अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही थी. उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर सपा के विधायक भारी अंतर से जीते हैं, वहां उम्मीदवारों को समय रहते चुनाव की तैयारी का मौका मिलना चाहिए. उदयवीर सिंह ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के साथ बातचीत जारी रहेगी और दोनों दलों के नेता मिलकर सीटों की अंतिम संख्या तय करेंगे.

आदेश के बावजूद दीपथून पर नहीं जला दीपक... विजय सरकार के खिलाफ दाखिल होगी अवमानना याचिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में दीपथून विवाद के मामले में तमिलनाडु सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका दाखिल कीजिए फिर देखेंगे. कोर्ट में बुधवार को तिरुप्परनकुंद्रम स्थित दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने के मामले को मेंशन किया गया. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील गुरु ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया और दीपथून पर दीप नहीं जलाया गया. वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने पीठ को बताया कि उन्हें घटनाक्रम से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी थी. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश दीपथून पर दीप नहीं जलाया जा सका.

इस पर वरिष्ठ वकील गुरु ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि निषेधाज्ञा लागू है और परंपराएं इसकी अनुमति नहीं देतीं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने की एक सुनियोजित कोशिश है. गुरु ने कहा कि दीपक की ज्योति ले जाकर दीपथून पर रखी जानी चाहिए थी. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार आखिरी समय तक हाईकोर्ट को यह भरोसा देती रही कि वह आदेश का पालन करेगी. इस दौरान वकील ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया. गुरु ने कहा कि वे राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल करेंगे.इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि आप अवमानना याचिका दाखिल कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे. इस मामले पर विश्व हिंदू परिषद ने तमिलनाडु पर मदुरै के पास तिरुप्परनकुंद्रम में कार्तिगई दीपम जलाने के मामले में विजय सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुद को ऊपर रखने का आरोप लगाया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि इससे न्यायपालिका की गरिमा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं. विहिप के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि तमिलनाडु में जो कुछ हुआ, ठीक उसी का मुझे डर था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी सर्वोच्चता थोपी है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगा दी और महिलाओं,बच्चों एवं बुजुर्गों सहित बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालुओं को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया.

ICC रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, दूसरे स्थान पर पहुंचे; रोहित शर्मा को नुकसान

नई दिल्ली। जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार गेंदबाजी की, जिसका फायदा उन्हें आईसीसी रैंकिंग में भी मिला है. टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में बुमराह ने 3 पायदान की छलांग लगाई है. वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप-3 में कोई बदलाव नहीं हुआ है. शुभमन गिल नंबर-1 बल्लेबाज बने हुए हैं. डेरिल मिचेल दूसरे और तीसरे नंबर पर विराट कोहली हैं. बेन डकेट 3 पायदान ऊपर आकर चौथे स्थान पर आ गए. रोहित शर्मा टॉप-5 से बाहर हो गए हैं.



तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 5 विकेट लिए थे. पहली पारी में उन्होंने 4 विकेट चटकाए थे. उन्होंने दोनों पारियों में टॉप लैथम को पहली पारी में शून्य पर आउट किया था. हालांकि भारत इस मैच को जीत नहीं सका, ये ड्रा पर खत्म हुआ. बुमराह ने रैंकिंग में 3 पायदान की छलांग लगाई है. ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज बने हुए हैं. उनकी रेटिंग 881 की है, जो उनके करियर की बेस्ट रेटिंग है. जसप्रीत बुमराह पांचवें से दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, उनकी 856 रेटिंग है. इंग्लैंड के ओली रॉबिंसन 2 पायदान ऊपर आकर तीसरे नंबर पर पहुंच गए. उनकी रेटिंग बुमराह के बराबर ही है. आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग के टॉप -5 में 1 बदलाव हुआ है. साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा चौथे से तीसरे और ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रेविस हेड तीसरे से चौथे नंबर पर पहुंच गए. नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज हैरी ब्रूक बने हुए हैं.

टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग के टॉप-5 क्रम में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है. साउथ अफ्रीका के मार्को जानसेन 440 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर है. रवींद्र जडेजा 414 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर हैं. साउथ अफ्रीका के वियान मुल्डर (294) तीसरे, बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज (276) चौथे और साइमन हार्मर (254) पांचवें नंबर पर हैं.

एयरपोर्ट-इन्फ्रास्ट्रक्चर समेत कई बड़े प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट की मंजूरी, 19 हजार करोड़ पास

नई दिल्ली। भारत बुल्डोजर, क्रेन और टनल बोरिंग मशीनों का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (25 नवंबर) को कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी. इसके लिए सरकार की तरफ से 19,934 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं. कैबिनेट ने पांच बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इक्विपेमेंट बनाने का डिसिजन सबसे बड़ा माना जा रहा है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. केंद्र सरकार ने देश में क्रेन और बुलडोजर समेत इन्फ्रास्ट्रक्चर



उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दी है. तमिलनाडु के कामराजार पोर्ट पर दूसरा कंटेनर टर्मिनल बनेगा. इसके लिए 4288 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं. वहीं असम के सिलचर स्थित डोलू में 2014 करोड़ रुपए से नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा.

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नया एयरपोर्ट बराक घाटी और आसपास के पूर्वोत्तर क्षेत्र को हवाई संपर्क उपलब्ध कराने के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा. फिलहाल सिलचर हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की देखरेख में है. वहां 70 एकड़ में फैले हिस्से से नागरिक विमान सेवाओं का संचालन होता है.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पहला मेक इन इंडिया से जुड़ा हुआ फैसला है. कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा इक्विपमेंट की जरूरत बढ़ती जा रही है. इनका निर्माण भारत में कैसे हो ये मेक इन इंडिया का अहम हिस्सा है. एक लाख करोड़ की डिमांड है. काफी आयात होता .इसमें आधे से ज्यादा भारत में निर्माण हों उद्देश्य है. 8 साल की योजना बनाई गई है. कुल 11 हजार करोड़ की योजना है.

'ये गुंडों, दंगाइयों का ठगबंधन, BJP को नहीं कोई खतरा'; कांग्रेस-सपा गठबंधन पर बिफरे डिप्टी CM

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी (SP)और कांग्रेस के गठबंधन को 'ठगबंधन' करार देते हुए बुधवार (25 नवंबर) को आरोप लगाया कि ये दोनों दल अपराधियों, दंगाइयों और भ्रष्ट तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मौर्य ने साथ ही दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) को ऐसे ठगबंधन से कोई खतरा नहीं है और पार्टी प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान मौर्य ने विपक्षी गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''यह कोई गठबंधन नहीं बल्कि गुंडों, अपराधियों, भ्रष्ट लोगों और दंगाइयों का 'ठगबंधन' है। इसकी हालत न तो आज अच्छी है और



न ही भविष्य में सुधरने वाली है। कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत के बीच सपा द्वारा पांच उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने के बारे में पूछे जाने पर मौर्य ने कहा कि यह दोनों विपक्षी दलों की अंदरूनी समस्याओं को दर्शाता है और इसका भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, ''दोनों दलों (सपा और कांग्रेस) के बीच इस तरह की नौटंकी होती रहती है लेकिन इससे भाजपा की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा।'' कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सपा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ। उनके इस बयान पर मौर्य ने कहा, ''अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा है तो उन्हें राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक है और वह भाजपा के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी।' उन्होंने कहा, ''समाजवादी पार्टी को वोट देना मुसीबत को न्योता देने जैसा है, जबकि कांग्रेस को वोट देना देश को फिर से पतन की ओर ले जाना होगा। जनता भाजपा के साथ मजबूती से खड़ी है और पार्टी उत्तर प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।'' मौर्य ने दावा किया कि सपा और कांग्रेस चाहे मिलकर चुनाव लड़ें या अलग-अलग, जीत भाजपा की ही होगी। उन्होंने कहा, ''इस 'ठगबंधन' का कोई भी व्यक्ति भाजपा के कमल को खिलने से नहीं रोक सकता।'' मौर्य ने सपा की ओर से घोषित पांच उम्मीदवारों में से तीन मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारे जाने पर निशाना साधा और पार्टी पर 'मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति' करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा उत्तर प्रदेश में फिर से दंगों का दौर और अपराधियों एवं माफियाओं का वर्चस्व लौटाना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि राज्य पिछले 10 वर्ष से दंगामुक्त रहा है। मौर्य ने कहा, ''कमल का बटन दबाने से उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहेगा। अगर लोग साइकिल का बटन दबाते हैं तो गुंडे, अपराधी और माफिया तत्व उनका शोषण करेंगे, उनकी जमीन हड़प लेंगे और उनकी बेटियों एवं महिलाओं को परेशान करेंगे।

उमर खालिद-शरजील इमाम को SC से जमानत नहीं, APA में ट्रायल की देरी के आधार पर फैसला करेगी 3 जजों की पीठ

नई दिल्ली। उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली है. इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम जमानत पर विचार करने से पहले दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनेंगे. कोर्ट ने बुधवार को 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आरोपी पूर्व छह स्कॉलर उमर खालिद की अंतरिम जमानत की मांग फिलहाल स्वीकार करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभी अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती. बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार



कर दिया था जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. 5 जनवरी 2026 को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने खालिद और शरजील को जमानत देने से मना कर दिया था. दोनों को कथित बड़ी साजिश का 'वैचारिक सूत्रधार' बताया गया था.वहीं इसी मामले में कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा सहित अन्य पांच आरोपियों को जमानत दे दी थी. कोर्ट ने कथित साजिश में उनकी भूमिका को उमर और शरजील की भूमिका से अलग माना था. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उमर खालिद और शरजील इमाम की ओर से अंतरिम जमानत की मांग पर जल्द विचार करने का अनुरोध किया.

परिसीमन बिल पर कांग्रेस का अमित शाह पर तंज, 'दो तिहाई बहुमत के लिए...'

नई दिल्ली। मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल को पारित कराने के लिए बहुमत जुटाने में लगी हुई है. सरकार ने अभी तक शीतकालीन सत्र का ऐलान नहीं किया है. सत्र का ऐलान न करने पर विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की अपनी बेताब कोशिश में हैं.

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके बताया कि चाणक्य ने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर लिया है मगर वो नाकाम रहे हैं.

जयराम रमेश ने लिखा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में साम, दाम, दंड और भेद का उल्लेख है. लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की अपनी बेताब कोशिश में. ताकि खतरनाक परिसीमन विधेयकों को पारित



कराया जा सके. खुद को चाणक्य मानने वाले इन साहब ने आखिरी तीन तरीकों (दाम, दंड और भेद) का सहारा लिया, लेकिन वे नाकाम रहे. क्यों न वे पहले तरीके (साम) को आजमाकर देखें?

उन्होंने आगे लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पिछले सात महीनों में- 11 अप्रैल, 16 जुलाई, 27 अगस्त और 16 अक्टूबर को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यही रास्ता अपनाने का सुझाव दिया है लेकिन इन पत्रों का कोई औपचारिक जवाब तक नहीं आया है.

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी सरकार पर बिल को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, इनका एक ही तरीका है कि किसी तरीके से कुछ मेजॉरिटी बनाकर टू थर्ड्स से अपने डीलिमिटेशन को पास करें. वो बहुमत इनके पास है नहीं. अब उसके लिए इन्होंने इधर उधर से खरीदना शुरू किया होगा. सौ दो सौ करोड़ प्रति सांसद जो भी इनके रेट होते हैं बांधे होंगे. हो सकता है अभी तक पूरी डीलिंग नहीं हुई होगी. जब डील हो जाएगी और इसके पहले कि दूसरा कहीं पैसे लेके भाग जाए उसके बीच में संसद का सत्र हो सकता है कर दें.

नोएडा में 6 लाख आबादी का एक और शहर बसेगा, न्यू नोएडा के बाद बागपत-खेकड़ा में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे किनारे बनेगी नई सिटी

नोएडाः नोएडा विस्तार के तीसरे चरण में खेकड़ा-बागपत एरिया में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के किनारे नया शहर बसाया जाएगा. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के किनारे खेकड़ा और बागपत में नोएडा पार्ट 3 बसाने की योजना है.नोएडा अथॉरिटी इसके लिए सर्वे करा रही है. रिपोर्ट शासन को स्वीकृति के लिए भेजी गई है. इससे पहले न्यू नोएडा को चार चरणों में बसाने की प्लानिंग पहले ही हो शुरू हो चुकी है. न्यू ग्रेटर नोएडा यानी ग्रेटर नोएडा फेज दो के मास्टर प्लान 2041 को भी सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है. दूसरे चरण में 140 नए गांवों के साथ उनकी जमीनों का अधिग्रहण होगा. इससे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के कुल गांवों की संख्या 257 हो जाएगी. इसमें गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर और गाजियाबाद के 140 गांव शामिल किए जाएंगे. ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान 2041 के हिसाब से शहर की आबादी अगले 15 साल में 40 लाख तक हो जाएगी.

दिल्ली-एनसीआर में न्यू नोएडा का दादरी-नोएडा-गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र (DNGIR) क्षेत्र है, जो गौतम बुद्ध नगर के दादरी और बुलंदशहर की सिकंदराबाद तहसील के गांवों की जमीन पर बनेगा.ये नया नोएडा शहर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के नजदीक होगा. इस शहर का लगभग 21 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल होगा.नया नोएडा के लिए पहले चरण में 87 गांवों की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है. इसमें बुलंदशहर के 60 और नोएडा के 27 गांव शामिल होंगे. लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत किसानों की जमीनों का अधिग्रहण होगा.

न्यू नोएडा के पहले चरण के लिए बुलंदशहर के 24 और गौतम बुद्ध नगर के 13 गांव शामिल हैं.किसानों को 4300 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा या 3800 और 7 फीसदी विकसित जमीन का विकल्प है. भूमि अधिग्रहण में तीन नए वर्क सर्किल बनाकर दो वरिष्ठ महाप्रबंधकों तैनात किए हैं. 18 अक्टूबर 2024 के बाद अधिसूचित गांवों में किसी भी निर्माण को पूरी तरह अवैध घोषित किया गया है.

सपा के 26 सीटों के ऑफर पर भड़के इमरान मसूद, बोले- 130 सीटों की लिस्ट में हमारी कई अहम सीटें ही नहीं



लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. सपा की ओर से कांग्रेस को 26 सीटों का प्रस्ताव दिए जाने और बातचीत के बीच पांच उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने पर मसूद ने कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस भिखारी है, जो सपा के दिए हुए ऑफर का इंतजार करती रहेगी? मसूद ने साफ कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सहयोगी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे चलने वाली पार्टी नहीं है।

इमरान मसूद ने कहा कि समाजवादी पार्टी किस आधार पर यह दावा कर रही है कि उसने सीट बंटवारे की शुरुआत 26 सीटों से की है? उन्होंने पिछले चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे दल भी थे, लेकिन नतीजा क्या निकला? वहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन भी कोई बड़ा राजनीतिक चमत्कार नहीं कर पाया था. कांग्रेस सांसद मसूद ने कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश में आए राजनीतिक बदलाव का फायदा मिला. राहुल गांधी और कांग्रेस ने बड़े दिल का परिचय देते हुए सपा को ज्यादा सीटें दी थीं, जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस चुनाव जीतकर आई. इसके बावजूद अब समाजवादी पार्टी जिस तरह का व्यवहार कर रही है, वह गठबंधन की भावना के अनुकूल नहीं है.

कांग्रेस सांसद ने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सहयोगी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे-पीछे चलने वाली पार्टी नहीं है. उन्होंने कहा कि गठबंधन में दोनों दलों को बराबरी और सम्मान के साथ बातचीत करनी चाहिए. सहारनपुर की सीटों पर सपा की ओर से उम्मीदवार घोषित किए जाने पर उन्होंने कहा कि मुद्दा सिर्फ सहारनपुर का नहीं, बल्कि गठबंधन में काम करने के तरीके का है. मसूद के मुताबिक, सपा ने जिन दो सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, वे 2017 में कांग्रेस के पास थीं. उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा और वह खुद पार्टी के निर्णय के अनुसार काम करेंगे.

हत्या के आरोपी का पहले हाथ काटा फिर बीच सड़क गोली मार फरार, पुणे कोर्ट के बाहर हॉरर



पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर दिनदहाड़े एक शख्स को कुछ हमलावरों ने घेर लिया. पहले उन्होंने मचेटी से उसका एक हाथ काट दिया. इसके बाद उसे गोली मारकर वहां से फरार हो गए. इस घटना के बाद कुछ देर तक वह शख्स फुटपाथ पर खून से लथपथ हालत में पड़ा रहा, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उसकी हालत क्रिटिकल बनी हुई है.

आंबेगांव पुलिस ने मंदार किवाले पर हुए हमले के मामले में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है. इस बात की जांच की जा रही है कि क्या हिरासत में लिए गए ये दोनों लोग आज के हमले में शामिल थे या उनका इस हमले से कोई सीधा संबंध है. आज की यह घटना अप्रैल 2025 के शुभम चव्हाण हत्याकांड से जुड़ी है और उस मामले से जुड़े कई लोगों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है.

इस मामले में संदिग्ध हमलावरों के तौर पर अक्षय चव्हाण, अमोल चव्हाण, पप्पू चव्हाण, सुभाष चव्हाण और एक अन्य साथी की पहचान की गई है.

अदालत के बाहर हुई इस वारदात की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. शिवाजीनगर पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल को घेर लिया और जांच शुरू कर दी. फिलहाल हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो सकी है.

पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात आपसी रंजिश का नतीजा थी या इसके पीछे कोई और कारण है. इस वक्त एक टीम आसपाल लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर हमलावरों की तलाश में भी जुटी है, ताकि उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

गोद में बच्चा लेकर ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में हिजाब वाली सांसद ने की बहस, लोग बोले- फिर दिल जीत लिया



नई दिल्ली। मां बनना कोई आसान काम नहीं है, और जब आप देश की संसद में बैठकर जनता की आवाज उठा रहे हों, तो यह चुनौती दोगुनी हो जाती है. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की संसद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा. निर्दलीय सीनेटर फातिमा पेमान अपनी नन्हीं बेटी आलिया को गोद में लेकर सीधे सदन की कार्यवाही में शामिल होने पहुंच गईं. संसद में डिजिटल सुरक्षा कानून पर गर्मागर्म बहस चल रही थी. इसी बीच जब फातिमा पेमान बोलने के लिए खड़ी हुईं, तो उनकी गोद में उनकी छोटी सी बेटी शांत बैठी थी. फातिमा ने बिना किसी झिझक के अपनी बात रखी और दुनिया को दिखाया कि एक मां अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल जिम्मेदारी को एक साथ कैसे निभा सकती है. 30 साल की फातिमा पेमान की कहानी सिर्फ संसद में बच्चा लाने तक सीमित नहीं है. उनकी जिंदगी का सफर बेहद संघर्षों भरा रहा है. अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जन्मीं फातिमा सिर्फ आठ साल की उम्र में रिफ्यूजी बनकर ऑस्ट्रेलिया पहुंची थीं. उनके पिता ने टैक्सी चलाकर और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके परिवार को पाला.

साल 2022 में फातिमा ने इतिहास रचा जब वह ऑस्ट्रेलिया की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली और सबसे युवा सांसदों में से एक बनीं. आज वह ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े सदन में बैठकर न केवल नीतियों पर बहस कर रही हैं, बल्कि कामकाजी माताओं के अधिकारों की सबसे बड़ी आवाज बन चुकी हैं.

दशकों से दुनिया भर की संसदें बेहद कड़े और पुराने नियमों से चलती आ रही हैं, जहां नई माताओं को बच्चों को घर छोड़कर आने की सलाह दी जाती थी.

दिल्ली में बनेगा तीसरा रिंग रोड, 121 करोड़ से बनेगा सर्विस रोड, अलीपुर से महिपालपुर तक मिलेगी हाईस्पीड



नई दिल्ली। दिल्ली के तीसरे रिंग रोड यानी कि अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) से सफर करने वाले लोगों को जल्द ही दो-लेन वाला सेकेंडरी सर्विस रोड मिलने जा रहा है. इसके बनने से हाईवे तक पहुंचना आसान हो जाएगा. NHAI, 121.57 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 12 महीने में यह रोड बनाएगी. इसका रखरखाव 10 सालों तक किया जाएगा. हालांकि इस लागत में GST और यूटिलिटी, जैसे बिजली, पानी, पाइपलाइन वगैहर के खर्च शामिल नहीं हैं.

अर्बन एक्सटेंशन रोड-II NH-344रूको दिल्ली का तीसरा रिंग रोड कहा जाता है. यह दिल्ली-एनसीआर में करीब 75-76 किमी. लंबा 6-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर है, जो कि अलीपुर (NH-44) से शुरू होकर उत्तर, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के प्रमुख इलाकों से होते हुए महिपालपुर के पास NH-48 (दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे) को जोड़ता है. NHAI सर्विस रोड दिल्ली में अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) के किनारे मौजूद राइट ऑफ वे के भीतर बनाने जा रहा है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय NHAI की मदद से दिल्ली में दो लेन वाला एक सेकेंडरी सर्विस रोड बनाने जा रहा है. यह प्रोजेक्ट 'इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन' (EPC) मॉडल के तहत पूरा किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट के लिए योग्य कॉन्ट्रेक्टर्स से बिड मांगी गई है. इसकी बोली 19 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जो कि 17 दिसंबर सुबह 11 बजे तक जारी रहेगी.इच्छुक ठेकेदार 'सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल' के जरिए अपनी बिड जमा कर सकते हैं.

यूपी चुनाव में ओमप्रकाश राजभर अपनी सीट बदलेंगे, गाजीपुर की जहूराबाद सीट छोड़ अकबरपुर से लड़ेंगे सुभासपा प्रमुख



लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा फैसला किया है. उन्होंने गाजीपुर जिले की जहूराबाद सीट छोड़ने का फैसला किया है और वो अकबरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. राजभर की पार्टी भाजपा की सहयोगी दल है और दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर वार्ता हो रही है. राजभर ने एक दिन पहले ही अपने दोनों पुत्रों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी. उन्होंने अतरौलिया विधानसभा सीट को लेकर अपनी पार्टी की दावेदारी पर बात रखी थी. ओपी राजभर अपने बेटे अरुण राजभर को अतरौलिया सीट से लड़ाना चाहते हैं. राजभर के एक बेटे की पिछले विधानसभा चुनाव में हार हुई थी. इस सीट को लेकर सुभासपा और निषाद पार्टी दोनों ही दावेदारी ठोक रही हैं. भाजपा दोनों सहयोगी दलों के बीच इस खींचतान को खत्म करने की कवायद में जुटी है. सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर (अरुण राजभर) को 2024 के लोकसभा चुनाव में घोसी सीट से हार का मुंह देखना पड़ा था. विधानसभा चुनाव 2022 में शिवपुर विधानसभा सीट भी वो जीत नहीं पाए थे. हालांकि अब वो अतरौलिया सीट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं. सीएम योगी ने राजभर की बात ध्यान से सुनी. बीजेपी नहीं चाहती कि सपा-कांग्रेस में जिस तरह सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद खुलकर सामने आए हैं, वैसा कोई सियासी संदेश एनडीए खेमे से भी जनता के बीच जाए. राजभर ने 6 दिसंबर को आजमगढ़ की सामाजिक समरसता महारैली में भी सीएम योगी को आमंत्रित किया है.

ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन में थी. उसने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, एक सीट पर वो सपा के सिंबल पर लड़ी थी. पार्टी ने छह सीटें जीती थीं. हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद राजभर एनडीए खेमे में आ गए थे. उन्हें यूपी की योगी सरकार में मंत्री भी बनाया गया. राजभर एनडीए में 20 से ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं.

'किसी और से शादी की तो मार दूंगा', युवती को होटल में रातभर बंधक बना कर रखा, भागी तो बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा



मेरठः उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के व्यस्त आबूलेन बाजार में एक युवती के साथ कथित तौर पर हुई मारपीट और बंधक बनाए जाने की घटना ने सनसनी फैला दी है. आरोप है कि सलमान नामक युवक ने युवती को काम के बहाने बुलाकर होटल में रातभर बंधक बनाकर रखा, दुष्कर्म किया और किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने पर जान से मारने की धमकी दी. मंगलवार को युवती होटल से भागकर बाहर निकली तो आरोपी उसके पीछे दौड़ा और कथित रूप से बाल पकड़कर उसे जबरन वापस ले जाने की कोशिश की. घटना मेरठ के आबूलेन बाजार स्थित होटल स्क्वायर की बताई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंगलवार दोपहर एक युवती मदद के लिए चिल्लाते हुए होटल से बाहर निकली. आरोप है कि उसके पीछे सलमान नाम का युवक भी दौड़ता हुआ आया और उसने युवती को पकड़ लिया. बताया गया कि युवक ने युवती के बाल पकड़कर उसे सड़क पर गिराया और वापस होटल ले जाने की कोशिश की. बाद में राहगीरों के हस्तक्षेप से युवती को आरोपी के कब्जे से छुड़ाया गया.

भारत में बन रही एशिया की सबसे लंबी सुरंग, 13 चस्लंबी जोजिला टनल, 15 मिनट में होगा कश्मीर से लद्दाख का सफर

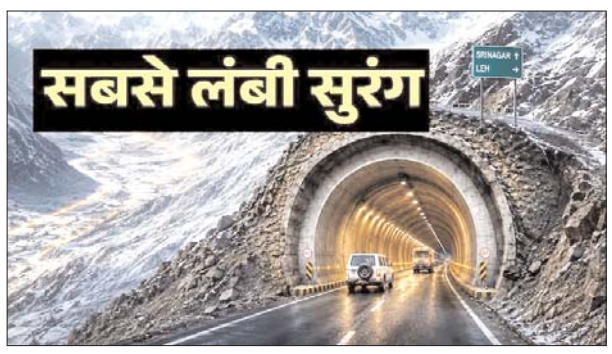

नई दिल्ली। भारत में बन रही एशिया की सबसे लंबी सुरंग की परियोजना अगले 6-8 महीनों में पूरी हो जाएगी. हम बात कर रहे हैं हिमालय के ऊंचे पर्वतीय दर्रे जोजिला में बन रही सुरंग की. जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है और कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है. 13 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग श्रीनगर और लद्दाख के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी देगी. इस प्रोजेक्ट पर यह बड़ा अपडेट खुद देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को दिया.

7वें वर्ल्ड लैंडस्लाइड फोरम को संबोधित करते हुए, नितिन गडकरी ने कहा कि हिमालय के नाजुक इलाकों में कनेक्टिविटी बनाने के लिए विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक सही संतुलन बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने अपडेट देते हुए कहा कि अभी तक जोजिला टनल प्रोजेक्ट का लगभग 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. यह प्रोजेक्ट अगले 6-8 महीनों में पूरा हो जाएगा. नितिन गडकरी ने आगे कहा कि हर प्रोजेक्ट को स्थानीय भू-विज्ञान (जियोलॉजी), जल-विज्ञान (हाइड्रोलॉजी) और ढलान की स्थिरता (स्लोप स्टेबिलिटी) की गहरी समझ के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें आधुनिक तकनीक और लंबे समय तक चलने वाली मॉनिटरिंग भी शामिल हो.

9 जून को जोजिला में एशिया की सबसे लंबी सुरंग परियोजना में एक बड़ी सफलता (ब्रेकथ्रू) हासिल हुई थी जब खुदाई का 13 किलोमीटर से अधिक काम पूरा हो गया. इस सफलता ने कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच 'हर मौसम में चालू रहने वाली कनेक्टिविटी' के दशकों पुराने सपने को हकीकत के और करीब ला दिया है. बता दें कि सुरंग बनाने के काम में, 'ब्रेकथ्रू' उस पल को कहते हैं जब दोनों तरफ से काम कर रही टीमें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती हैं.

9.5 मीटर चौड़ी, 7.57 मीटर ऊंची और 13.153 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 'हॉर्सशू' यानी घोड़े की नाल के आकार की है. यह एक सिंगल-ट्यूब, दो-लेन वाली सड़क सुरंग है, जिसे समुद्र तल से लगभग 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है.

बचत खाते पर RBI रेट से भी इतना पर्सेंट ज्यादा ब्याज देगा स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, जल्द लॉन्च होगा नया फीचर



नई दिल्लीः अगर आप सेविंग्स अकाउंट पर ज्यादा ब्याज कमाना चाहते हैं तो आपके लिए एक नया मौका आने वाला है. दरअसल, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक (Slice Small Finance Bank) ग्राहकों के लिए एक नया फीचर लाने की तैयारी कर रहा है. बैंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है. बैंक के मुताबिक, जल्द ही ग्राहकों को अपने पैसे पर पहले से ज्यादा कमाई करने का मौका मिलेगा.

स्लाइस ने अपने पोस्ट में 'Slice S' की झलक दिखाई है. इसके साथ लिखा है, '115% repo on savings set aside' यानी सेविंग्स अकाउंट में अलग रखी गई रकम पर रेपो रेट का 115 फीसदी ब्याज मिलेगा. हालांकि, बैंक ने अभी यह साफ नहीं किया है कि यह सुविधा कब से शुरू होगी और इसके लिए क्या शर्तें होंगी?

फिलहाल स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने सेविंग्स अकाउंट पर आरबीआई के रेपो रेट के बराबर ब्याज देता है. अभी रेपो रेट 5.5 फीसदी है. इस हिसाब से ग्राहकों को सेविंग्स अकाउंट पर 5.5 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है. इतना ही नही यह बैंक अपने ग्राहकों के खाते में रोजाना ब्याज देता है. मान लीजिए कि आपके स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के खाते में 2 लाख रुपये हैं तो 5.5 फीसदी सालाना ब्याज के हिसाब से आपके अकाउंट में करीब 30 रुपये ब्याज रोजाना मिलेंगे.

बैंक की ओर से शेयर किए गए पोस्ट के मुताबिक, स्द्यद्बष्द्ग स में सिर्फ सेविंग्स पर ज्यादा ब्याज ही नहीं, बल्कि दूसरे फायदे भी मिल सकते हैं. पोस्ट में 115 फीसदी रेपो रेट के बराबर ब्याज, वीजा क्रेडिट कार्ड पर जीरो फॉरेक्स चार्ज और ट्रैवल बुकिंग पर 5 गुना रिवॉर्ड जैसे फायदों का जिक्र किया गया है. हालांकि, इन सुविधाओं से जुड़ी जानकारी, नियम और शर्तें अभी सामने नहीं आई हैं. बैंक ने फिलहाल इसे जल्द लॉन्च होने वाली सुविधा के तौर पर पेश किया है.

सपा का तंज- दो सीट वालों को जो मिल रहा है, चुपचाप ले लें, भड़की कांग्रेस करने लगी मायावती की तारीफ



लखनऊः यूपी चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर मंथन के बीच ही सपा की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी किए जाने पर बवाल मचा हुआ है. दोनों दलों से कुछ नेता फायर मोड में हैं तो वहीं कुछ लोग गठबंधन में पड़ी गांठ को खोलना चाहते हैं. इस बीच सपा के सांसद एसपी सिंह पटेल ने कांग्रेस पर तीखा तंज कसा है और दो सीटों वाली पार्टी बता दिया है. इसके अलावा उन्होंने इमरान मसूद की बयानबाजी को भी कांग्रेस नेतृत्व की साजिश करार दिया. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इमरान मसूद से दबाव बनवाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व बयानबाज़ी करवा रही है. वहीं सपा की ओर से कैंडिडेट तय करने पर भड़की कांग्रेस मायावती की तारीफ करने लगी है. कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने मायावती की तारीफ की है. इसके अलावा मायावती या फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार भी नहीं किया है. इसके अलावा उन्होंने फिर से भरोसा जताया कि हमें 100 से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी. गौतम ने कहा कि वार्ता के बीच में सीटों का ऐलान करना गैर-जिम्मेदाराना है. अखिलेश यादव के खुले खत पर गौतम ने कहा कि मैंने उसे पढ़ा नहीं है. हमें किसी की भी सलाह की जरूरत नहीं है. गौतम ने मसूद का भी बचाव किया और कहा कि वह सांसद हैं और उन्हें हक है कि नाराजगी जाहिर करें. अमेठी और रायबरेली की सीटों पर भी राजेंद्र पाल गौतम ने बात की. उनका कहना था कि अभी तो वार्ता चल ही रही है. इन जिलों पर भी बात की जाएगी. उधर, एसपी सिंह पटेल एकदम फायर मोड में दिखे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति ये है कि अकेले चुनाव लड़ लें तो एक सीट ना जीत पायें. उन्होंने कहा कि दो विधायकों वाली पार्टी को जो मिल रहा है वो चुपचाप ले लेना चाहिए, बड़बोलेपन से नुकसान उन्हीं का है. एसपी सिंह पटेल ने कहा कि गठबंधन में बहुत होगा तो दस पांच सीटें और दे दी जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं. एसपी सिंह पटेल पर इमरान मसूद के बयान पर उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी की बदौलत नहीं बल्कि अपने नेता अखिलेश यादव की वजह से सांसद बना हूं. कांग्रेस को पहले अपने आंकड़ों पर नज़र डालनी चाहिए, उसके बाद बयान देना चाहिए.

अमेरिका का खसरा मुक्त दर्जा खत्म, जमकर फैला प्रकोप

वॉशिंगटन। खसरे का संक्रमण एक बार फिर दुनिया के कई देशों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। बांग्लादेश में इस बीमारी से बड़ी संख्या में लोगों की मौत के बाद अब अमेरिका में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि अमेरिका में करीब 26 साल पहले खसरे को खत्म घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब यह संक्रमण दोबारा व्यापक स्तर पर फैलने लगा है। पिछले 12 महीनों से लगातार संक्रमण बने रहने के कारण अमेरिका ने अपना खसरा-मुक्त दर्जा भी गंवा दिया है। अमेरिका में भी हालात चिंताजनक हैं। एक स्वास्थ्य संगठन ने पुष्टि की है कि देश में खसरे का वायरस कम से कम 12 महीनों से लगातार फैल रहा है। इसी आधार पर 17 नवंबर को अमेरिका का खसरा-मुक्त दर्जा समाप्त हो गया।

रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार, पिछले सप्ताह ही 426 नए मामले सामने आए। इस साल देशभर में अब तक 5,800 से अधिक संक्रमण दर्ज किए जा चुके हैं।

स्वामी/ प्रकाशक / मुद्रक
प्रमोद कुमार ने जय माँ गंगा प्रिंटर्स, हरिद्वार से मुद्रित कराकर कार्तिकेय कॉलोनी, फेस-3, दर्पण स्कूल वाली गली, निकट हनुमान मंदिर, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी जनपद-नैनीताल (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया।
सम्पादक
प्रमोद कुमार
मो.7830201066
सह-सम्पादक
दया जोशी
मो.9412135616